Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Undertakings of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 1969 and ending on the 30th April,, 1970 and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, five members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

MOTION FOR ELECTION TO COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI K. RAGHURAMAIAH): Madam, I beg to move the following Motion:

"That this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that the Rajya Sabha do agree to nominate seven members from the Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts of the Lok Sabha for the term beginning on the 1st May, 1969 and ending on the 30th April, 1970 and do proceed to elect, in such manner as the Chairman may direct, seven members from among the members of the House to serve on the said Committee."

The question was put and the motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The programme of election to the Committee on Public Accounts and Committee on Public Undertakings will be published in Parliamentary Bulletin.

We go to the Legislative Business.

THE APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI): Madam, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain 14—6 RSS/ND/69 sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1969-70, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Madam, this Bill provides for the withdrawal from the Consolidated Fund of India of the amounts required to meet the expenditure charged on the Fund and the grants voted by the Lok Sabha. The figures have been given in detail in the budget papers which have been submitted. Excluding the payment of States' share of Union excise duties and repayment of public debt which are no-tionally shown as expenditure charged on the Consolidated Fund, the net disbursements to be made from the Consolidated Fund amount to Rs. 4,847 crores. Of this, Rs. 1,605 crores represent the provision for Plan expenditure, Rs. 615 crores for Central assistance to the States for their Plan schemes, Rs. 117 crores for the Centrally sponsored schemes, Rs. 65 crores for Union Territory Plan schemes, and Rs. 808 crores for the Central Plan proper.

In addition, Rs. 133 crores will be spent by the Railways for their Plan outlay, and Rs. 165 crores extra would be spent by the public sector undertakings including the Railways and the Posts and Telegraphs. Besides this, the non-Plan provision amounts to Rs. 3,242 crores of which Rs. 1,110 crores are for Defence and the balance of Rs. 2,132 crores are for Civil Expenditure.

Madam, I need not go at this stage into the various details of these expenditures. After the debate is over, I will try to reply to the various points raised by the hon. Members.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Antani. Your name is here on the Appropriation Bill.

DR. B. N. ANTANI (Gujarat): I have to speak tomorrow.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Thengari is not here. Mr. Yadav. Mr. Man Singh Varma. Nobody is ready. Mr. Lakshmana Gowda. Nobody is prepared to speak.

(Interruptions)

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: Dr. Antani is speaking.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Dr. Antani, are you speaking?

SHRI SITARAM JAIPURIA (Ut-tar Pradesh): Madam, Prof. Ruth-naswamy will be here at*any time.

DR. B. N. ANTANI: I will get up and say something.

(After a pause)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Dr. Antani, you do not want to speak?

SHRI SUNDAR SINGH BHAN-DARI: He is speaking.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let me know whether he is speaking.

(After a pause)

Mr. Kulkarni. He is also not willing to speak. I think nobody is willing to .speak.

Mr. Yajec. Mr. Adinarayana Reddy, Mrs. Mehta, Mr. Syed Hus-sain, Mr. Kemparaj, Mr. Purnanand Chetia. No one in the list is ready.

(Interruptions)

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): I am to speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: When I called out the names, nobody was ready.

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: No, no. How can I understand? You called all names together and I could not follow.

THE DEPUTY CHAIRMAN; I looked at you,

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: I will speak.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right, speak. But when names are called out, nobody is prepared . . .

(Interruptions)

श्री शीलभद्र याजी : मैडम डिप्टी चेयरमैन, मैं बोल रहा हूं।

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : पहले तो इधर से।

श्री शीलभद्र याजी : चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताये का होत है।

मैडम डिप्टी चेयरमैन महोदया, मैं इस एप्रोप्रिएशन बिल का समर्थन करता हूं और समर्थन करते हुए मैं तमाम सदस्यों को यह कहना चाहता हूं कि जब जब बजट में कर की वृद्धि का प्रोपोजल आता है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं और इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि मेरी यह राय है कि जब तक हिन्दुस्तान के जो, जितने, रिसोर्सेज़ हैं उन सब का संग्रह न करें तब तक हमारी जो प्लानिंग है, योजना है वह कभी भी सफलीभूत नहीं हो सकती। बदकिस्मती है कि हमारी वैसी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है और इसलिए हमें विदेशों से कर्जा लेना पड़ता है—विदेशों से कर्जा लेना कोई शर्म की बात नहीं है, सब सरकारें लेती है और उससे काम चलाती हैं लेकिन हमारा बराबर यह निजी विचार रहा है कि देश में जो टैक्स देने वाले हैं उनसे टैक्स लिया जाय और अमीरों से ज्यादा लिया जाय तथा गरीबों से कम लिया जाय। यह हमारा विचार बराबर रहा है। लेकिन मेरी शिकायत है कि अभी जो हमारी सरकार है वह समाजवाद की स्थापना करने के लिये बात करती है किन्तु इसकी जो आर्थिक नीति है वह मिक्सड एकानामी की है, गंगा-जमुना की

नीति है श्रौर यह जो गंगा-जमुना की नीति है वह मुल्क के लिये अच्छी चीज़ नहीं है। कितने दिन तक यह चलेगी यह तो पता नहीं। श्रौर इसीलिये हमारी सरकार कभी कभी श्रमीरों पर रहम करती है। उनसे तो इतना टैक्स लेना चाहिये कि हमें बाहर के जो देश हैं उनसे कर्जा लेने की जरूरत न पड़े। इसके साथ ही साथ जो मध्य-वित्तीय दर्जे के लोग हैं, जिनकी माली हालत श्रच्छी है, उनसे भी जरूर टैक्स लिया जाय श्रौर गरीबों से कम लिया जाय। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। जो हमारी समाजवाद की नीति है वह तो श्रपनी जगह पर सही है, प्लानिंग भी, योजना भी, हम करते हैं लेकिन जो हमारी श्रार्थिक नीति है वह गलत है श्रौर जो मिक्सड इकानामी की नीति है उसको ही हम ढोहे चले जा रहे हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि चूंकि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानते हैं इसलिए मिक्सड इकानामी रखे हुए हैं। दुनिया में जो भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की परिभाषा है उसे हमने पढ़ा है लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब दलील देते हैं वह समझ में नहीं आती है। डमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है? यह कि डेमोक्रेटिक मेथड से उसकी स्थापना करेंगे श्रौर इसलिए ही उसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं लेकिन डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में टाटा भी रहेंगे, बिड़ला भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं वह भी रहेंगे, तो यह तो कभी चलता नहीं है। लेकिन चल रहा है। सरकार को इस नीति का परित्याग करना पड़ेगा श्रौर जब तक वह इस नीति का परित्याग नहीं करती है तब तक सोशलिज्म की स्थापना नहीं होगी श्रौर तब तक हमारी जो माली हालत है वह कभी सुधरने वाली नहीं है।

इसलिये हम श्रपनी सरकार से बराबर कहते हैं कि जो बड़े बड़े कल-कारखाने हैं, जो बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, की श्रौर बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, सब का जल्दी से जल्दी समाजीकरण करना चाहिये श्रौर उनको मुश्राविजा, कम्पेनसेशन, नहीं देना चाहिये। लेकिन जब तक यह जो मौजूदा कांस्टीट्युशन है, संविधान है, उसमें जब तक कि मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक तो हमें कम्पेनसेशन देना ही पड़ेगा, इसलिए हमारी सरकार से यह दरख्वास्त है कि यदि वह सचमुच में समाजवाद की स्थापना करना चाहती है तो जल्दी से जल्दी जो हमारा संविधान है, कांस्टीट्युशन है, उसमें रैडिकल श्रमेंडमेंट होना चाहिये, मौलिक तरमीम होनी चाहिये श्रौर मौलिक तरमीम कर के जो मुश्राविजा की, कम्पेनसेशन देने की बात है उसको हटाना चाहिये।

श्री सीताराम जैपुरिया : यह एप्रोप्रिएशन बिल है।

श्री शीलभद्र याजी : हां, यही तो है, इसमें श्रार्थिक नीति है। मैं उनके मन के मुताबिक ही यह बात नहीं बोल रहा हूं। मुझे बोलने दीजिये।

तो जब तक हम उसमें मौलिक परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हमारी श्रार्थिक हालत नहीं सुधर सकती है श्रौर इसीलिये हमारी सरकार से बराबर मांग होती है कि इसमें जब तक मौलिक परिवर्तन नहीं होगा तब तक समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। चूंकि इसमें कम्पेनसेशन का क्लाज़ है श्रौर जब तक कम्पेनसेशन की, मुश्राविजा देने की, क्षतिपूर्ति देने की जो व्यवस्था है उसको हम हटा नहीं देंगे तब तक हमारे देश में कभी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती है। इसलिये मैं फिर उस बात

[श्री शीलभद्र याजी]

को दुहराता हूं कि ये जो सभी बड़े बड़े कल-कारखाने हैं उन सब का जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं होगा बिना मुआ-विजा दिये हुये तब तक हमारी आर्थिक स्थिति कभी भी सुधर नहीं सकती है इसलिए आर्थिक हालत को सुधारने के लिये यह काम जल्दी से जल्दी होना चाहिये। लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक सुझाव है। जो स्वतंत्र पार्टी के लोग हैं वह जो चिल्ल-पों मचाते हैं कि पब्लिक सेक्टर तरक्की नहीं कर रहा है तो इसमें हमारी सरकार भी कभी कभी गलती करती है क्योंकि ये जो आई० ए० एस०, आई० पी० एस० हैं, अफसर लोग हैं, जिनको बिजनेस और इंडस्ट्रीज चलाने की तमीज़ नहीं है, ज्ञान नहीं है, उनको वह वहां बैठाती है, तो मेरी यह राय है कि जब हम सभी चीजों का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो उन्हीं टाटा को, बिड़ला को या बड़े बड़े सेठों को, सिंघानिया को, जैपुरिया जी को, जो कि यहां बैठे हुये हैं उनको बैठायें । यहां जैपुरिया जी बैठे हैं बाबूभाई चिनाई भी बैठे हुये हैं, ऐसे ऐसे लोगों को . . .

श्री सीताराम जैपुरिया : आप जैपुरिया की चिन्ता मत कीजिये।

श्री शीलभद्र याजी : जो बिजनेस चलाने वाले हैं, जिनको बिजनेस चलाने का ज्ञान है उनको ही यह इंडस्ट्री चलाने के लिए सरकार को नौकर बनाना चाहिये और नौकर बना कर के इनको ज्यादा से ज्यादा 5 हजार या 10 हजार रु० तनख्वाह देनी चाहिये जैसा कि लेनिन ने किया था, रेवोल्युशन होने के बाद उसने इसे आफिसरों को नहीं दिया, उन्हीं पूंजीपतियों को दिया, जिनसे उसको लिया था उनको बड़ी बड़ी तन-ख्वाहें दे कर के, सैलरी दे कर के रखा, चूंकि वह इंडस्ट्री का हाल जानते थे इसलिये उन इंडस्ट्रीज़ को उनसे चलवाया। इसलिए हमारी सरकार को भी चाहिये कि जब जब किसी चीज़ का वह राष्ट्रीय-करण करें तो यह न देखे कि दूसरे लोग क्या आपत्ति करते हैं बल्कि उनको ही वहां रखें। इन्हीं पूंजीपतियों को नौकर बनाकर और काफी पैसा देकर उन कामों में लगाया जाय ताकि उनको महसूस न हो क्योंकि हिन्दुस्तान में कहावत मशहूर है कि लड़का मर जाता है, उसका ग़म लोग बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन पैसा तथा धन चला जाता है तो उनकी नानी मर जाती है, बड़ा अफसोस होता है। इसलिये उनको काफी पैसा देकर, नौकर बनाकर, मैनेजर बनाकर, जनरल मैनेजर बनाकर, हम उनसे इंडस्ट्री चलवायेंगे और हमारी पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो यह बात होती है कि घाटे में जा रही हैं तो वह बात किसी को सुनने का सवाल भी नहीं आयेगा। असल में घाटा नहीं होता है लेकिन चिल्ल-पों यह मचाते हैं। स्वतंत्र पार्टी के कुछ लोग हैं जो पूंजीपतियों के ठेकेदार हैं, उनकी तरफ से कभी कभी आवाज़ उठती है कि यह सब घाटे में जा रहा है और इस क़दर आवाज चली कि हममें से भी कुछ लोग भ्रांति के शिकार हो गये हैं, कि पब्लिक सेक्टर फायदा नहीं कर रहा है। इस लिये आयंदा से यह कोशिश होनी चाहिये कि जिस भी इन्डस्ट्री का, उद्योग का, हम राष्ट्रीयकरण करें या समाजीकरण करें, हम उन्हीं लोगों के हाथ में दें और उन्हीं लोगों को लाएं जिनको इन्डस्ट्री चलाने का ज्ञान हो और अच्छी तरह से चला सकें।

इसके साथ साथ हमको स्टेट फाइ-नेन्स मिनिस्टर से एक निवेदन करना है कि एक बार सरकार ने यह तय किया, और बड़ी कोशिश के बाद, पच्चीस वर्ष

के बाद, तय हुआ कि जो हमारी आज़ाद हिन्द फौज के लोग है, उनके जो एरियर्स थे, उनका जो बकिऔटा बाकी था, जो बहुत दिनों से उनका जमा था— मैं समझता हूं 1 करोड़ 10 लाख रु० होंगे —बड़ी कोशिश के बाद यह तय हुआ डिफेन्स मिनिस्ट्री से और सरकार से कि यह जो आई० एन० ए० के लोग हैं, जो तीन तरह के लोग थे ब्लैक, व्हाइट और ब्राऊन, तो ब्रिटिश गवर्नमेन्ट ने ब्राउनों को दे दिया, व्हाइट्स को दे दिया लेकिन "ब्लैक्स" जिन लोगों ने हमारी आजादी की लड़ाई लड़ी हम लोगों के साथ, और हमने सही काम किया था, यह कहा उनको अंग्रेजों ने उस समय उनका बकिऔटा बंद कर दिया लेकिन जब हमारी नेशनल गवर्नमेन्ट हो गई और हमारे आज़ाद हिन्द फौज के 3 लाख सिपाही जिनमें से 26 हजार लोग शहीद हुए, उन शहीदों के नाम पर आप गद्दी में बैठें, आई० एन० ए० के लोगों की नौकरी आपने ले ली, उनको सेना में नहीं जाने दिया, वह कोई काम के नहीं रह गये, और उनका जो बकऔटा था वह नहीं दिया। अंग्रेजों को तो आपने सूद दर सूद देकर विदा कर दिया लेकिन जो हमारे आज़ाद हिन्द फौज के लोग आज गली गली में मारे फिरते हैं, सिर्फ 1 करोड़ 10 लाख रु० बकऔटा है, तो जब आपने तय किया—दिया जाय, तो कैसे दिया जाय? आप देंगे क्या ? पेपर बोन्ड। आप वन फोर्थ कैश देने जा रहे हैं और इसके बाद उनको आप कागज के पेपर बोन्ड देंगे, पेपर बोन्ड उनको पकड़ा देंगे।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : आप किस तरह से देना चाहते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : हम सरकार को अपील कर रहे हैं कि वह सब एकदबार कैश के रूप में दे दें। (*Time bell rings*) आपको समझ में नहीं आ रहा है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Please wind up.

श्री शीलभद्र याजी : अभी तो आधा घंटा चाहिये।

श्री श्री० ए० अहमद (उत्तर प्रदेश) : मैं भी बोलना चाहता हूं।

श्री शीलभद्र याजी : मैडम, आपने एक दर्जन नाम पुकारे। वह लोग बोलने के लिये तैयार नहीं थे। मुझको सबका समय दे दीजिए। हमको ज़रा आज़ाद हिन्द फौज के लिये कहने दीजिए।

इसलिये जो आज़ाद हिन्द फौज के लोगों का बकऔटा है जो सूद दर सूद 26 वर्ष में दुगुना हो गया है, तो आप दुगुना न देकर जितना भी रुपया उनका बकऔटा है उसमें भी आप किश्त पर देना चाहते हैं। यह ठीक नहीं है। इसलिए उनको पेपर बोन्ड न देकर नकद जितना उनका बकऔटा है दे दिया जाय और जल्दी दिया जाय।

इसके साथ साथ, अभी तक हमारे नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भस्मि जापान में रखी हुई है, जो नेताजी दो बार कांग्रेस के प्रेसीडेन्ट रह चुके, अभी तक उनकी भस्मि टोकियो में रखी हुई है। सरकार के लिये उचित यह था कि नेताजी की भस्मि को राष्ट्रीय सम्मान देकर यहां लाया जाता। अब भी हमारी सरकार कहती है कि पंडित नेहरू जी ने इसके बारे में उनके परिवार के लोगों से बात कर ली लेकिन उनके परिवार के लोग नहीं चाहते थे। तो क्या नेताजी किसी एक परिवार के हैं?

[श्री शीलभद्र याजी]

वह सारे हिन्दुस्तान के परिवार के हैं, सारे राष्ट्र के हैं और यह बड़े कलंक की बात है, शर्म की बात है कि उनकी भस्मि तो वहां रखी रहे और हम उसको लाएं नहीं और जापान में रखी रहे और जापान के लोग यह समझते हैं कि शायद नेताजी को हिन्दुस्तान के लोग इज्जत नहीं देना चाहते हैं। इस लिये सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जापान में जो नेताजी की भस्मि रखी हुई है, उसको लाकर और उसको सारे हिन्दुस्तान में घुमा कर उनको इज्जत दें। आजाद हिन्द फौज की वजह से, नेताजी की वजह से, आज़ादी को लाने में सहायता हुई है। इसलिये उनको सम्मान अवश्य मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं फिर, सरकार ने जितने टैक्स लगाये हैं, उनका समर्थन करते हुए सरकार से कहता हूं कि जितनी उसमें रियायत कर दी है वह कर दी है लेकिन हमें बाहर से भिक्षा नहीं मांगनी है, गरीब और अमीर सब के ऊपर टैक्स लगाकर हमें अपनी योजनाएं, प्लानिंग, चलानी हैं। जय हिन्द।

श्री जेड० ए० अहमद: उपसभापति महोदया, इस बजट में कुछ खास बातें ऐसी आई हैं जो मुझे खटकीं और सबसे मुख्य बात जिस तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं वह यह है कि खेतिहर या किसान जनता के ऊपर और उनकी पैदावार के साधनों पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई। मैं समझता हूं कि यह शुरुआत है, एक नये सिलसिले की शुरुआत है, और उसके पीछे एक समझ है। वह समझ यह है कि विकास के कारण, जितना विकास हमारे देश में हुआ है, किसान बहुत सुखी हुआ, किसान के पास बहुत सी खरीदने की शक्ति बढ़ी है और उस ख़रीदने की शक्ति को जिसको कि अंग्रेजी में "मौप अप" कहते हैं—लूट लिया जाय, उसको खींच लिया जाय, उठा लिया जाय—यह आज एक राष्ट्रीय आवश्यकता हो गई—मैं इस थियरी की समझ को ग़लत समझता हूं। मैं समझता हूं कि बजाय इसके कि आज अरबों रुपया विकास पर खर्च किया गया है लेकिन साधारण किसान की हालत कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। मैं आंकड़े पेश कर सकता हूं और मैं समझता हूं उन आंकड़ों को देखना चाहिये कि औसत आमदनी शहर के लोगों की क्या है और किसान की क्या है। मैं उन इलाकों को या खित्तों को छोड़ देता हूं जो इस ज़माने में बहुत विकसित हो गये हैं, उदाहरण के तौर पर हमारे पश्चिमी यू० पी० के कुछ इलाके या आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके या महाराष्ट्र के कुछ इलाके या पंजाब के कुछ खित्ते। उनको मैं छोड़े देता हूं चूंकि वहां जो विकास हुआ है वह एक आम रूल नहीं है। साधारण तौर पर हर जगह उस तरह का विकास नहीं हुआ है। हिन्दुस्तान के अधिकतर जगहों में खेती अभी तक छोटे छोटे किसानों के हाथ में है, यानी ऐसे किसान जो अपनी जीविका के लिये, अपने रहन-सहन के लिये पूरी तौर पर उस पर निर्भर नहीं कर सकते, उनको कुछ और काम करना पड़ता है, उनको खेती के अलावा कहीं मजदूरी करनी पड़ती है, उनको मुलाज़मत करनी पड़ती है, छोटा मोटा व्यापार करना पड़ता है, उनको दूध बेचना पड़ता है, इस प्रकार के धंधे उन्हें करने पड़ते हैं। अगर हम दुनिया के दूसरे मुल्कों के साथ मुक़ाबला करें तो हम देखते हैं कि हमारे देश में हमारे खेतिहर समाज, छोटे किसानों का समाज है और आंकड़े भी बताते हैं कि लगभग 80 फी सदी किसानों के पास 5 एकड़ से कम जमीन है। तो इसलिये यह कहना

कि खेती की बड़ी उन्नति हो गई, बहुत बड़े पैमाने पर किसान पैदा करने लगा है और उसको बड़ी क़ीमतें मिलने लगी हैं, इसलिये वह बहुत सुखी हो गया है और इतना सुखी हो गया है कि जो उसके पास धन आता है उसमें से उसका अतिरिक्त धन आप करों की शक्ल में खींच लें और विकास के रूप में इस्तेमाल करें, मैं समझता हूं यह थियरी ग़लत है।

मैं खास तौर पर इस बात पर तवज्जह दिलाना चाहता हूं, मेरी धारणा यह है कि एक नया सिलसिला शुरू हुआ आज इस बजट में, हल्के से कुछ टैक्स इन्ट्रोड्यूस कर दिये गये हैं, पम्पिंग सेट के ऊपर टैक्स लगा है, खाद के ऊपर टैक्स लगा है, वेल्थ टैक्स के नाम पर किसानों पर टैक्स लगाने की कोशिश की गई, और अगर इसको रोका न जाये, तो यह सिलसिला आगे बढ़ता चला जायेगा, बड़ी आसानी से आप इसको आगे खींचते ले जायेंगे। अखबारों में इस के बारे में काफी शोर व गुल मचा कि इस टैक्स में परिवर्तन किया जाय। लेकिन क्या आप समझते हैं कि इस तरह के टैक्स से किसान लोग सुखी होंगे? सरकार किसानों से रुपया खींचना चाहती है और मैं समझता हूं कि यह एक गलत चीज़ है। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे टैक्सों से बचना चाहते हैं और इसीलिए वे कहते हैं कि यह टैक्स जो लगाया जा रहा है वह ठीक है। लेकिन वे अपनी बचत के लिए कि हमें उद्योग-धन्धों में उन्नति करना है, हमें काफी रुपया मिलना चाहिये ताकि उद्योग-धन्धे बढ़ें, इसलिए वे इस तरह के टैक्स की हिमायत भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उद्योग-धन्धे काफी बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हमारी खेती की जो तरक्की होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है।

आज हमारे मुल्क में ग्रीन रिवोल्यूशन की बात की जाती है, लेकिन मैं इसको बकवास समझता हूं। हिन्दुस्तान में कोई ग्रीन रिवोल्यूशन नहीं हो रहा है। आप गांवों पर चले जाइये। आपको वही पुराने फटे हाल किसान दिखलाई देंगे। आप उनके पास फटी हुई धोती देखेंगे, पांवों पर चप्पल नहीं मिलेगी, इधर उधर खाने के लिए फिरते रहते हैं और खेती के लिए वह साहूकार से कर्जा लेता है। इस तरह आज उसकी हालत है और वह जिन्दगी भर कर्ज में ही फंसा रहता है।

वह अपनी खेती के लिए एक बैल भी नहीं खरीद सकता है और आज हमारे मुल्क में 80 और 90 परसेंट किसानों की ऐसी ही हालत है। केवल 10 परसेंट ऐसे किसान हैं जिनके पास ट्रेक्टर खरीदने के लिए पैसा हैं और उसके जरिये वे खेती करते हैं। इस तरह के जो 10 परसेंट किसान हैं उन्हें कोआपरेटिव बैंकों से कर्जा भी मिल जाता है मगर जो छोटे किसान हैं उन्हें अपनी खेती करने के लिए कोई भी साधन नहीं मिलते हैं और न ही किसी प्रकार का कोई कर्जा ही मिलता है। इस तरह से जो 90 परसेंट हमारे मुल्क में किसान हैं, छोटे किसान हैं वे इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। बजाय इन किसानों से साधन खींचे जाय उन्हें साधन देना चाहिये। हमारे बजट का और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का यह काम होना चाहिये कि दूसरी जगहों से साधन लेकर उनको देते ताकि वे अपनी खेती की उन्नति कर सकते।

आज आप ग्रीन रिवोल्यूशन की बातें करते हैं। हम भी चाहते हैं कि इस मुल्क में ग्रीन रिवोल्यूशन हो, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बुनियादी चीजें

[श्री जेड० ए० अहमद]

खेती करने के लिए हैं जो बुनिग्रादी साधन हैं, वे हमारे किसानों को मिलने चाहिये। ग्राज हम देख रहे हैं कि हमारे मुल्क में खेती का जो तौर-तरीका है वह तेजी से नहीं बदल रहा है। किसानों के पास जो पुराने ग्रौजार थे वे ही ग्राज भी हैं ग्रौर यही कारण है कि हमारे मुल्क में ग्रन्न का संकट होता है ग्रौर यही कारण है कि ग्राज मंडियों के ग्रन्दर संकट पैदा हो जाता है। हमारे मुल्क में जो किसान हैं, जो देहात में रहता है उसकी तादाद करीब 70 या 75 परसेंट है। ग्राज उसके पास खरीदने की शक्ति नहीं रह गई है। वे ग्राज ग्रपनी खेती के लिए न बैल खरीद सकते हैं, न ग्रौजार, सीमेंट, ईंट ग्रौर बीज खरीद सकते हैं ग्रौर न कोई दूसरी चीज ही खरीद सकते हैं। इसकी वजह से वह खेती में तरक्की नहीं कर सकता है ग्रौर इसका ग्राखिरी नतीजा यह होता है कि हमारे जो उद्योग हैं वे एक संकट में फंस जाते हैं क्योंकि वे जो माल बनाते हैं वह बिक नहीं पाता है। ग्राप उद्योग-धन्धों को बढ़ाते ही चले जा रहे हैं ग्रौर ग्राम जनता की खरीदने की शक्ति को नहीं बढ़ायेंगे तो मुल्क में हर तरह का संकट ग्रायेगा। ग्रगर ग्राप उद्योग-धन्धों की ग्रोर ज्यादा तवज्जो देंगे तो इनका सरपलस प्रोडक्शन हो जायेगा जिससे वह बिक नहीं सकेगा।

ग्राप ग्रीन रिवोल्यूशन चाहते हैं लेकिन मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि सरकार के जो तौर तरीके हैं वे ऐसे नहीं हैं जिसकी वजह से इस मुल्क में ग्रीन रिवोल्यूशन हो सके। ग्राज सब से बड़ा सवाल छोटे किसानों का है। क्या ग्राप ग्राज उनकी हालत को जानते हैं। मुझे इनके बारे में काफी बड़ी दिलचस्पी है। मैं जब ब्लाक्स में जाता हूं तो देखता हूं कि खेती के जितने भी साधन होते हैं वे जो बड़े बड़े किसान या फार्मर होते हैं वे ले लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि जितनी भी कोग्रापरेटिव सोसाइटियां हैं वे छोटे किसानों को कितना कर्जा देती हैं। ग्राज यह कहा जाता है कि छोटे किसानों को कोग्रापरेटिव सोसाइटियों द्वारा कर्जा मिलना चाहिये। जो भूमिहीन किसान हैं, जो शेयर क्रापिंग करते हैं, किसी तरह से खेती करते है, उनको कोग्रापरेटिव सोसाइटीज किसान ही नहीं मानती है। जो छोटे किसान हैं उन्हें किसी तरह का ऋण नहीं मिलता है, उनको किसी तरह का कर्जा नहीं मिलता है। इसी तरह के हमारे मुल्क में ज्यादातर किसान हैं जिन्हें किसी तरह की सहूलियत नहीं मिलती है। ग्राज वे हर तरह से परेशान हैं ग्रौर फिर भी ग्राप उन के ऊपर टैक्स लगाते हैं जो कि एक भयंकर बात है। ग्रगर ग्राप खेती के ऊपर टैक्स लगाते हैं तो ग्राप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे खेती में उन्नति कर सकेंगे। जो खेती करने के मुख्य साधन हैं, जिनके जरिये छोटा किसान ज्यादा उपज कर सकता है उनको ग्राप सस्ता करें। ग्राज किसानों को खाद महंगे दामों पर मिलती है तो वे किस तरह से ज्यादा खेती कर सकेंगे। ग्राज हमारे मुल्क में जो खाद की कीमत है वह दूसरे मुल्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। हम तो इस बात की हमेशा शिकायत करते ग्राये हैं कि इस को सस्ता किया जाय। इसको इतना सस्ता किया जाय कि जो 1 एकड़ वाला, 2 एकड़ वाला ग्रौर 3 एकड़ वाला किसान है वह भी खुले तौर पर इसको ग्रासानी से खरीदकर इस्तेमाल कर सके। ग्राप इस तरह की बात नहीं करते हैं बल्कि उल्टे उन पर टैक्स लगाते हैं।

जो छोटे छोटे किसान हैं, जो 5 हार्स पावर के पम्पिग सेट इस्तेमाल करते हैं, उनके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हैं। एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो इंग्लैंड के थे, उन्होंने मुझ से कहा था कि आप के पावों के नीचे तो महासागर है, खोदिये, छेद कीजिये, तो आपको पानी मिल जायेगा। लेकिन जब पम्पिग सेट किसानों ने लगाने शुरू किये तो उनके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। कहां सरकार को किसानों को खेती की उपज बढ़ाने के लिए हर तरह की मदद देनी चाहिये थी मगर हमारे यहां तो उल्टी गंगा बहती है। इसका नतीजा यह हुआ कि हालत बद से बदतर होती जा रही है। मेरा कहना है कि इस थ्योरी को नहीं मानना चाहिये और छोटे किसानों के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिये जो वैल्थ टैक्स के नाम पर लगाया जा रहा है। आप प्रदेशों की सरकारों को यह अधिकार क्यों नहीं देते कि वे इस तरह का टैक्स लगायें। आप ए०जी० की राय लेकर क्यों बीच में कूद पड़े। यह तो स्टेट सब्जेक्ट था और आपको इसमें दखल नहीं देना चाहिये था। आज तो स्टेट आप से कर्जा लेकर जिन्दा है, लेकिन आज आप उन्हीं का रुपया खींचकर किसी को भी दे देना चहते हैं।

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): That is to help the States.

श्री जेड० ए० अहमद : वह हेल्प नहीं है। जो पैसा जब में डाल देता है वह फिर आसानी से नहीं देता है। जब मैं पैसा जेब में डाल दूंगा तो दूसरे से कहूंगा कि भीख मांगो, मेरे सामने आओ और मांगो। मैं जितना देना चाहूंगा उतना ही उन्हें दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। क्या यह मदद करने का तरीका है। मदद करने का तरीका यह है कि आप सीधे तौर पर और खुले तौर पर उनकी मदद करते और जो उनके लिए साधन है उनमें आसानी पहुंचाते। इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक वेल्थ टैक्स का सवाल है उसमें गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिये था और न ही उसको इसमें ए० जी० को लाना चाहिये था। इसमें सवाल ए० जी० का नहीं है, सवाल कानून का नहीं है। इस में तो सवाल जिन्दगी का है। इसमें सवाल गांव वालों का है, प्रदेश वालों का है जिन्हें आप भूखा मारना चाहते हैं। हमारी दिल्ली सरकार का आफिसर कहता है कि दिल्ली आओ, फकीर बनकर आओ और हमें सलाम करो और तब हम तुम्हें कुछ भीख दे देंगे। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक इस वेल्थ टैक्स का सवाल है इसको खत्म किया जाना चाहिये। आपकी जो नीति छोटे किसानों के मुतल्लिक है वह बदलनी चाहिये। आज कांग्रेस सरकार की जो नीति है वह किसान-विरोधी है। आज कांग्रेस सरकार की जो नीति है वह बड़े बड़े उद्योग-धन्धों को मदद करने की है। हमारे जयपुरिया साहब हंस रहे हैं वहां पर बैठकर। मैं समझता हूं कि आपको बहुत फायदा होता है। जयपुरिया जी की तरह जितने भी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें इस कांग्रेस की सरकार के जरिये बहुत फायदा पहुंच रहा है और वे उससे बहुत संतुष्ट रहते हैं। मैं सोचता हूं कि जो गरीब किसान 5 एकड़ वाले हैं, अगर सरकार उनकी सहायता करती है तो इसका नतीजा यह होगा कि हमारी खेती की पैदावार 25 परसेंट बढ़ जायेंगी। जयपुरिया साहब फले-फूले, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उनके फलने फूलने के साथ गरीबों की भी भलाई होनी चाहिये।

श्री निरंजन वर्मा : अब कितना फूलेंगे।

श्री ज़ेड० ए० अहमद : मैं इसके साथ ही साथ यह सुझाव देना चाहता हूं कि बजट के अन्दर एक नया नजरिया, एक नया दृष्टिकोण होना चाहिये, जो हमें नहीं मिल रहा है। विकास की 3 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई हैं। चौथी योजना की रूपरेखा बन रही है और वह चलनी शुरू होगी और उसमें अरबों रुपया खर्च होगा। आज कसौटी यह देखनी है कि जितना रुपया योजनाओं पर खर्च होता है उससे हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या हासिल करते हैं। मैं समझता हूं कि जितना रुपया योजनाओं के नाम पर बजट में मांगा जाता है उसकी आधी रकम खर्च होती है और वह भी जाया हो जाती है।

आप जिलों में चले जाइये और देखिये वहां पर क्या होता है। जहां पहले एक अफसर था वहां पर 10 अफसर हो गये हैं। जहां पहले एक डिपार्टमेंट था वहां पर 10 डिपार्टमेंट हो गये हैं। जहां एक सेक्रेटरी बैठा था, वहां पर ज्वाइन्ट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी हो गये है और इस तरह से सेक्रेटरीज की कतार बन गई है। जहां नौकरशाही बढ़ गई है वहां कायदे कानून भी बढ़ गये हैं। मैंने यू० पी० में जो ब्लाक्स हैं वहां देखा है, जो रूरल ब्लाक्स हैं वे मध्य प्रदेश में तो खत्म कर दिये गये हैं, मगर दूसरी जगहों पर ब्लाक्स अभी कायम ही हैं और उनमें काफी रुपया खर्च होता है। यू० पी० असेम्बली ने एक समिति बनाई थी जिसका मैं चेयरमैन था। हम लोग गये और ब्लाक्स को एग्जामिन किया।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I think you can continue after lunch.

SHRI Z. A. AHMAD: Only two minutes I shall take. I have to go to another meeting. That is why I requested you to allow me to speak now.

THE DEPUTY CHAIRMAN: All right.

श्री ज़ेड० ए० अहमद : मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहता हूं कि विकास के नाम पर क्या क्या तमाशा हुआ। वह रूरल डेवलपमेंट ब्लाक्स की जो कमेटी थी उसमें हम कई जगह पर गये। उसमें हमने एक बी० डी० ओ० से पूछा कि आप के यहां पैदावार कैसी बढ़ रही है तो वे कहने लगे कि पैदावार बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने उनसे कहा कि आंकड़े दिखाइये तो वे कहने लगे कि देखिये साहब तीन साल पहले हमारे क्षेत्र में इतनी पैदावार थी, फिर इतने मन हुई और यकायक कर्व जो होता है वह बढ़ता चला जा रहा है। हमने कहा कि बी० डी० ओ० साहब, आप बताइये कि आप अन्दाज़ा कैसे करते हैं। कहने लगे कि कोई बात नहीं है, यह कोई मुश्किल बात नहीं है। हमने कहा कि कैसे! तो कहने लगे कि सरकार ने एक स्केल हमें दे रखा है और वह स्केल यह है कि अगर एक कच्चा कुआं खोदा जाता है तो समझिये कि पैदावार सौ मन बढ़ गई, अगर पक्का कुआं खोदा जाता है तो समझिये दो सौ मन बढ़ गई और अगर ट्यूबवैल लगाया जाता है किसी जगह पर तो समझिये कि तीन हज़ार मन बढ़ गई, अगर खाद इतनी लग गई तो समझिये कि इतनी पैदावार बढ़ गई और अगर कहीं पर बिजली थी और अगले साल वह डेवढ़ी हो गई तो समझिये कि डेढ़ गुनी या दो गुनी पैदावार बढ़ गई। इस तरह वे कहने लगे कि यह बड़ा आसान काम है। हम को सरकार ने एक स्केल दे

रखा है, हम को कमिश्नर साहब ने, डाइरेक्टर साहब ने एक स्केल दे रखा है और उसी हिसाब से दफ्तर में बैठ कर हम आंकड़े दे देते हैं। जितने कच्चे कुएं खोदे जाते हैं, जितनी सड़कें बनती हैं, जितने ट्यूबवैल बनते हैं, जितनी खाद लगती है उसी हिसाब से काल-कुलेट कर के हम आंकड़े भेज देते हैं कि इतनी पैदावार हमारी बढ़ गई। कमाल की बात है। बिल्कुल अनरियलिस्टीक प्लान है। कहीं जा कर वे आंकड़े नहीं देते हैं कि कितना पैदा हो रहा है। आज जो खाद दी जाती है वह कभी कभी खेती को उलट देती है, उसको जला देती है क्योंकि आप खाद दे रहे हैं तो पानी नहीं दे रहे हैं और पानी दे रहे हैं तो खाद नहीं दे रहे हैं। यह कौन सा तरीका है कि सरकार नौकरशाही के हाथ में प्लानिंग को दे और जनता का सहयोग न ले। जो जनता के नुमाइन्दे हैं उनसे आज बात नहीं की जाती है। हम जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आप गड़बड़ करने आते हैं, इस तरह से प्लानिंग नहीं होगी।

इस लिये मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमें अपने नज़रिये को बदलना है, दृष्टिकोण को बदलना है। हमारा बजट हिन्दुस्तान में 80, 85 फीसदी जो देहातों में रहने वाले छोटे किसान हैं, मध्यम दर्जे के किसान हैं, मज़दूर हैं, साधारण कारोबार करने वाले लोग हैं, उनके हित में होना चाहिये। हमें उनको सामने रखना चाहिये, न कि जयपुरिया साहब को सामने रखना चाहिये या बड़े बड़े पूंजीपतियों को सामने रखना चाहिये। उनको भी कुछ दिया जाय, लेकिन वे इस देश के मालिक नहीं हैं, इस देश की रीढ़ की हड्डी नहीं हैं। हमारे देश का भविष्य उन करोड़ों इंसानों की जिन्दगी के साथ जुड़ा हुआ है जो कि देहातों में रहते हैं। इस लिये बुनियादी तौर पर हमें अपने नज़रिये को बदलना चाहिये और नये प्रकार का बजट बनाना चाहिये। यही मेरी आलोचना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: The House stands adjourned till 2 P.M.

The House then adjourned for lunch at four minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at two of the clock—THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI JAISUKHLAL HATHI): Madam, I have discussed with the various Leaders of the Opposition Groups. I would suggest that instead of four days, we may finish this Bill in three days, namely, on the 6th 7th and 8th May 1969. They are all agreeable.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that we should finish this Bill in three days?

HON. MEMBERS: Yes.

श्री निरंजन वर्मा: माननीया, सदन के सामन यह विनियोग विधयक क्रमांक 3 आया है और इसमें यह व्यवस्था दी गई है कि भारतवर्ष की संचित पूंजी में से एक अरब और 60 करोड़ रुपए से अधिक धन निकाला जाय और उनको भारतवर्ष की उन सेवाओं पर खर्च किया जाय जो अनुसूची में अंकित हैं। उदाहरण के लिए, जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती मित्रों ने कहा है, सम्भवतः इस विनियोग विधेयक में जिन जिन कार्यों के लिए और जिन मंत्रालयों के लिए जितने धन की आवश्यकता है उनकी यहां पर एक सूची दी गई है।

इस वर्ष 1968 की अपेक्षा जो विशेषता रही है वह यह है कि जब

[श्री निरंजन वर्मा]:-
से बजट ग्राया है तब से भारतवर्ष में सारे किसानों के लिए ग्रौर उन दूसरे मित्रों के लिए जो किसानी करते रहे हैं उनके सामने एक प्रश्न रहा है ग्रौर वह प्रश्न यह रहा है कि उनकी सरकार ग्रौर उसके कुछ बोलने वाले जब तक यह बात कहते फिर रहे हैं कि देश में एक ग्रीन रिवोल्यूशन ग्राना चाहिए या ग्रीन रिवोल्यूशन ग्रा रहा है। इससे पूर्व भी कांग्रेस पक्ष की ग्रोर से समय समय पर इसी प्रकार के नारे दिए गए। कभी यह कहा गया कि 'ग्राराम हराम है', कभी यह कहा गया कि 'जय किसान, जय जवान' ग्रौर ग्रब तीसरा नारा 'ग्रीन रिवोल्यूशन' का ग्राया है। हम समझते हैं कि इस नारे में कोई दम नहीं है। इस नारे में इसलिए कोई दम नहीं है क्योंकि यह नारा देखने में बहुत ग्राकर्षक, बहुत सुन्दर है लेकिन इसके पीछे तथ्य बिलकुल नहीं है।

किसानों के ऊपर टैक्स लगाने की मंत्रिमंडल के द्वारा ग्रौर कांग्रेस के उन मित्रों के द्वारा जो बात कही गई है वे मित्र कभी खेती करते नहीं हैं ग्रौर न खेती के बारे में जानकारी ही रखते है। मंत्री के स्तर का कांग्रेस हाई कमान्ड का कोई व्यक्ति ग्रपने बंगले की क्यारियों में थोड़ी बहुत मिर्च बो दे तो उससे यह नहीं माना जायगा कि वह खेती करने में बहुत कुशल व्यक्ति है ग्रौर ग्रभी यही बात है। ग्रादरणीया, भारतवर्ष में खेती का जो सबसे बड़ा प्रश्न चल रहा है वह दो बातों के ऊपर ग्राधारित है ग्रौर यह कृषि की समस्या न होकर खाद्य की समस्या भी है। प्रति वर्ष हम खाद्य के रूप में बाहर से करोड़ों रुपयों का ग्रनाज मंगाते हैं ग्रौर ग्रनाज का उत्पादन करने के लिए हम प्रति वर्ष करोड़ों रुपयों का खाद मंगाते हैं, फटिलाइजर मंगाते हैं। कांग्रेस सरकार की तरफ से गत 20 वर्षों में हमारे सामने बार-बार कहा गया है, यह बात दोहराई गई है कि ग्रब भारतवर्ष में हम बहुत जल्दी खाद्य के मामले में ग्रात्म-निर्भर हो जाएंगे, हमको खाद्य की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, लेकिन "जस-जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दुगुन कपि रूप दिखावा"। रामायण में यह चौपाई है। कांग्रेसी मित्रों ने जितने जोर-शोर से यह कहा कि हम खाद्य की समस्या सुलझा रहे हैं उतना ही खाद्य की समस्या उलझती गई।

श्री शीलभद्र याजी : सुरसा की तरह पापुलेशन बढ़ रही है।

श्री निरंजन वर्मा : पापुलेशन की जो बात कही जाती है उसके मामले में हम यह निवेदन करते हैं कि एक बार परिवार नियोजन के बारे में ग्रौर पापुलेशन के बारे में जब सारे संसार में चर्चा चल रही थी तो हमारे योग्य मित्र श्री शील-भद्र याजी को याद रखना चाहिए कि उस समय रूस के पत्र प्रावदा ने ग्रालोचना करते हुए क्या लिखा था। उसने लिखा था कि हमारे सामने यह समस्या नहीं है कि संसार में कितने ग्रादमी बढ़ते चले जा रहे हैं ग्रौर न इस समस्या की तरफ हमने ध्यान दिया, हमारे सामने समस्या यह है कि जितनी ग्राबादी है उस ग्राबादी के ग्रनुरूप हम संसार में बाहर जाकर उनके उपयोग सोचें, उनका विकास किस तरह से हो सकता है उसके लिए नए नए तरीके खोजें ग्रौर नए नए तरीकों से जो हमारी समस्याएं हैं उनको हल करें। जो लोग नए तरीके नहीं खोज सकते, जो लोग नए उद्योग-धन्धे नहीं लगा सकते, वे केवल ग्रपनी जनसंख्या के ऊपर बैठे रहते हैं ग्रौर उसी की बात को बार-बार दोहराते रहते हैं। रूस देश के प्रावदा समाचार-पत्र की यह ग्रालोचना हमारे मित्रों को ध्यान में रखनी चाहिए।

इस विनियोग विधेयक में 2 अरब 70 करोड़ 61 लाख 79 हजार हमने परचेज आफ फूड ग्रेन्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए रखा है। यह बहुत दुख की बात है। जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं उनके लिए लज्जा की बात है कि इतना रुपया बाहर भेजने के बाद भी प्रतिवर्ष हम फूड ग्रेन्स मंगाते रहते हैं और खाद को भी हम आयात करते रहते हैं। इस वर्ष जब यह सम्भावना थी कि हमारे देश में खाद की बहुत सी उत्पादन समितियां बन गई हैं और उनके द्वारा स्थान-स्थान पर सिन्द्री आदि स्थानों पर खाद का उत्पादन हो रहा है तो हमें कल्पना यह करनी चाहिए थी कि हमारे देश में खाद इतनी सुलभ, इतनी सस्ती और हर किसान के घर में जाने वाली हो जायगी कि इससे हम खाद्य की समस्या सुलझा सकेंगे लेकिन खाद्य की समस्या सुलझने की बात तो अलग रही, खाद के मामले में हम और टैक्स लगाते चले जा रहे हैं।

अभी हमारे कृषि मंत्रालय की तरफ से सारे भारतवर्ष के राज्यों के किसानों को ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत एक लुभावना, दूर से अच्छा दिखने वाला पैम्फलेट फेंका गया और उसमें यह बताया गया—शंकर मिश्रित जो बीज है गेहूं का सोनारा या मेक्सिको उसको कोई किसान बो दे तो वह किसान सौ गुने तक प्राप्त कर सकता है। हमारे यहां मध्य प्रदेश में इसके विषय में अनुसंधान हुआ और हम यह निवेदन करते हैं कि यह जो बात है यह बिल्कुल असफल हुई। मध्य-प्रदेश के बहुत से किसान एक-एक, दो-दो बीघे के किसान नहीं हैं। एक-एक, दो-दो बिघे के जो किसान हैं अगर उन्हें सोनारा या मेक्सिको तरह के बीज दे दिए जायं तो सम्भव है कि वे एक किलो से लेकर 50 किलो तक, 100 किलो तक पैदा कर सकते हैं लेकिन जिनके पास 50-50, 100-100, 200 200 बीघे जमीनें हैं या बड़े-बड़े फार्म हैं, वहां पर यह नितान्त असम्भव है, कभी सम्भव होने वाली बात नहीं है कि 50 गुना या 60 गुना पैदावार हो सके। उसके कारण स्पष्ट हैं। एक तो यह कि सरकार ने इस बीज को देने के पूर्व इस बात का अनुसंधान नहीं किया और न इस बात का यत्न किया कि किसानों के पास इस बीज को देने के बाद पानी की समस्या का हल कर लिया गया है या नहीं। दूसरी बात यह है कि किसानों को बीज देने के बाद जो उर्वरक, खाद देना चाहिये वह खाद उन को सस्ती मिलनी चाहिये थी, किन्तु वह और महंगी हो गयी है जिस के कारण किसान जितना लाभ उनको बतलाना चाहिये था वह उतना लाभ बतला नहीं सकेंगे और सन् 1969-70 का वर्ष कृषि के लिये उसी प्रकार से खराब रहेगा, बल्कि और भी ज्यादा खराब रहेगा और देश खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेगा और संभवतः हमें बाहर से अन्न की भिक्षा फिर लेनी पड़ेगी। अन्न की भिक्षा के लिये बाहर के देश हिन्दुस्तान के लिये कोई अच्छी ओपीनियन नहीं रखते हैं। बाहर के बहुत से देशों में हिन्दुस्तान के लिये समाचार-पत्रों में जो टिप्पणियां आती हैं उन को पढ़ने से विदित होता है कि भारतवर्ष के लोगों को वह आलसी समझते हैं या उद्योग से रहित समझते हैं जिस के कारण कि वह इतने दिनों के बाद भी अपनी समस्याओं को हल नहीं कर पाये हैं।

इसी प्रकार आदरणीया, इस में कुछ और बातों की ओर उल्लेख करने की आवश्यकता है। हमारे देश में इस समय दो, तीन बातों की ओर ध्यान

[श्री निरंजन वर्मा]:

देना अत्यन्त आवश्यक है। इस देश में रहने वाले जितने नागरिक हैं, जितना इस देश में रहने वाली जनता का आबादी का बड़ा हिस्सा है, उसको, निश्चित रूप से सब को, मकान, जिसे आवास कहते हैं, भोजन और वस्त्रों की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी बागीचे को बहुत सुन्दर सुन्दर पुष्पों से सजाया जाय और उस में अच्छे रंग-बिरंगे फूल रख दिये जायं तो उसके बाद भी एक समस्या यह रहती है कि उस पूरे बागीचे की रक्षा किस प्रकार से की जाय। हम यह तो नहीं कह सकते कि कांग्रेस के महाप्रभुओं ने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम यह अवश्य कहते हैं कि जितना ध्यान दिया जाना चाहिये था उतना ध्यान नहीं दिया गया। आज से चार, पांच दिन पूर्व हमारी आदरणीया प्रधान मंत्री ने हमारे एक मित्र के प्रश्न के ऊपर, जब वह प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया कि चीन से हमारी दुश्मनी है और चीन अगर कभी हवाई हमले के साथ अणु हमला करने को तैयार हो तो हमारी जनता को बचाने के लिये क्या सरकार के पास कोई साधन है, प्रधान मंत्री ने इसको टाल दिया और उन्होंने उसका यह उत्तर दिया कि इस से संसार में बड़े युद्ध की आशा की जा सकती है। संसार में बड़ा युद्ध हो या न हो, थोड़ी देर से भी अगर हो, यह मान लीजिये, लेकिन संसार के बड़े बड़े राष्ट्र जब तक हमारी सहायता को आयेंगे तब तक तो भारतवर्ष विनाश के कगार पर पहुंच चुका होगा और उस समय अगर बाहर के देश आये अणु युद्ध प्रारम्भ करने के लिये तो उस समय तक हमारी समस्या कहां चली जायगी इस बारे में देश के कर्णधारों ने कोई विचार नहीं किया। इस विनियोग विधेयक में डिफेंस के लिये भी रुपये की मांग की गयी है और इस के अतिरिक्त उन्होंने 90 वें आइटम में एटामिक इनर्जी के लिये भी रुपये की मांग की है और इस के बाद उन्होंने 133वें मद में कैपिटल आउट ले के बारे में एटामिक इनर्जी के बारे में मांग की है। हम समझते हैं कि सारा देश आज इस मामले में एक मत है कि हमें किसी दूसरे की रक्षा पर विश्वास न करते हुए, किसी के विश्वास पर, किसी के यत्नों पर पूरी तरह से विश्वास न करते हुए केवल अपने ऊपर, अपने आत्म-विश्वास पर खड़े रहना चाहिये और उस के लिये सारा भारतवर्ष आज यह चाहता है कि भगवान न करे, लेकिन यदि कभी ऐसी स्थिति आये, जैसे आज दूसरे देश बराबर घुड़दौड़ करते चले जा रहे हैं अस्त्र शस्त्रों की प्रतियोगिता में और जो सब से बड़ा हमारा मित्र रूस था वह भी पाकिस्तान को बराबर अस्त्र शस्त्र दे रहा है, तो उसके लिये हमें अणु बम बनाना चाहिये। इस के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं रहता।

इसके अतिरिक्त इसमें और जो मांगें हैं उन के बारे में भी शासन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एक तो हमारी सफलता हमारे इस चरित्र के ऊपर निर्भर करती है कि हम संसार के साथ किस प्रकार का व्यवहार रखते हैं। कोई माननीय सदस्य पार्लियामेंट में घुसते समय केवल यह वाक्य पढ़ लेने के बाद, जो कि पार्लियामेंट के एक आर्च पर लिखा हुआ है—वसुधैव कुटुम्बकम्, यह नारा लगाये कि हम सारे संसार को एक कुटुम्ब के समान मानते हैं तो वह एक मृग-तृष्णा में रहेगा। वह भारी गलती करेगा। संसार में जो बड़े बड़े राष्ट्र हैं वह अपनी लाभ और हानि के आधार पर दूसरे राष्ट्रों से मित्रता करते हैं। अगर भारतवर्ष

से उन्हें कोई लाभ की अपेक्षा होगी तो इस से मित्रता करेंगे और अगर इस से उन को हानि की आशंका होगी अथवा हमारा राष्ट्र निर्बल रहा तो हमारे साथ वह मित्रता नहीं करेंगे और हमारी मित्रता से कतरा कर वह दूसरे देशों के गले में अपनी बांहें डालने का यत्न करेंगे। इस के लिये दूसरे राष्ट्रों को अपना मित्र बनाने का काम, आदरणीया, हमारे राजदूतों पर निर्भर करता है। हमें बहुत से राजदूतों के बारे में पता है। हमारा विदेश विभाग सोता रहता है और इस विदेश विभाग में हमारे राज-दूतों के लिये कुछ नियम हैं। वह नियम अंग्रेजों की देन हैं। हमने स्वयं ही अपने नियमों का कोई विकास नहीं किया। भारतवर्ष के बाहर जब हमारे राजदूत जाते हैं तो उनको चार, पांच बातें स्मरण रखना चाहिये। एक तो यह कि जिस देश की ओर से वह राजदूत हो कर जा रहे हैं उस देश की संस्कृति क्या है और उस संस्कृति के विरोध में उन्हें कभी कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाना चाहिये। दूसरी बात यह है कि जिस देश के वह राजदूत हो कर जा रहे हैं उस देश की वेश-भूषा क्या है, उस की आमदनी क्या है, उस देश में उन का जो विकास का एक मार्ग है वह कितना अवरुद्ध है, इस के बारे में भी उन को सोचना चाहिये और तीसरी बात यह है कि जिस देश में जो राजदूत जायं वे वहां की भाषा पर अपना अधिकार रखें। यह नहीं होना चाहिये कि यहां से जो राजदूत जाते हैं वे केवल अंग्रेजी भाषा बोलने में ही माहिर हों। स्पेन में गये तो स्पेन की भाषा नहीं बोल सकते और उन्हें इस बात का सबक लेना चाहिये कि अभी पिछले दिनों स्पेन के राजदूत भारत में आये और उस ने यहां आ कर अपना परिचय पत्र दिया— हिन्दी भाषा में दिया। क्या इस से हम यह शिक्षा नहीं ले सकते कि अमरीका में, आस्ट्रेलिया में, कनाडा में और इंग्लैंड में, जहां पर अंग्रेजी चलती है वहां तो अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग जायं, लेकिन जर्मनी में, फ्रांस में या रूस में या और दूसरे देशों में जो हमारे राजदूत जायं तो उन को वहां की भाषा में निष्णात होना चाहिये और हमारी भाषा में उन को निष्णात होना चाहिये। इस के साथ साथ वे जब कभी हमारी सरकार से पत्र-व्यवहार आदि करें या वार्तालाप आदि करें तो वह उन को अपने देश की भाषा में करना चाहिये, किसी दूसरे देश की भाषा में उन को बात नहीं करनी चाहिये।

आदरणीया, अभी कुछ समय पहले सांची में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और वहां पर संसार के लगभग 8, 10 राष्ट्रपति और राजदूत और बहुत से प्रतिनिधि आये थे। वहां एक विशेषता-थी कि जिस देश का जो आदमी आता था चाहे वह बर्मा का हो या कंबोडिया का, वह चाहे वियतनाम का हो अथवा चीन का, या वह पश्चिम के देशों का हो, वे सब अपने देश की वेश-भूषा में थे और सब अपने देश की वाणी में बात करते थे। जब कभी किसी दूसरे से बात करने की आवश्यकता हुई तो एक इंटरप्रेटर रहता था। लेकिन हमारे यहां हम ने सब कुछ छोड़ दिया है और इस की वजह से ही हमारी संस्कृति का ह्रास हो रहा है, बराबर होता चला जा रहा है। इसी प्रकार हमारे यहां के राजदूतों को अधिक ऐश्वर्य के साधन भी नहीं दिये जाने चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Your party has forty minutes in all. You have taken twenty minutes so far. There are two other speakers from your own party. You may take

[The Deputy Chairman]
all the time and it depends on you how the total time is to be shared by your party members.

श्री निरंजन वर्मा : आदरणीया, इसी तरह से एक बात की ओर मैं और सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा। हमारे देश में इतिहास समाप्त हो गया है। हमारे पास इतिहास नहीं रहा। जो कुछ भी हमारे पास इतिहास है वह बाहर के देशों ने जो कुछ लिखा है उस के आधार पर ही अपने देश के इतिहास का हम ने निर्माण किया है। अपने देश के वास्तविक इतिहास का पता अगर हमें चल सकता है तो वह आर्क्येलाजी की सहायता से ही चल सकता है और इस की ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पूरे भारतवर्ष में सब से प्राचीन अगर कोई स्मारक है, कोई आर्केलाजिकल स्थान है तो वह सांची है लेकिन भारतवर्ष की सरकार ने सांची का, जहां कि आज से 25 सौ वर्ष पुरानी इतिहास की वस्तुएं हैं और स्तूप हैं, पूर्ण रूप से निरादर किया है। न तो वहां पर विमान उतरने की व्यवस्था है, न वहां पर विमान के जाने की व्यवस्था है और न वहां पर लोगों को पीने के पानी का भी साधन है। वहां पर कोई बगीचा नहीं है, वहां पर पानी नहीं है, वहां पर कोई अच्छा भोजनालय नहीं है और इस तरह से सारे संसार के आदमी उस स्थान को देखने के लिये आते हैं लेकिन वहां से निराश जाते हैं। हमारी सरकार ने आगरा और दिल्ली इन दोनों स्थानों को छोड़ कर के जो आर्केलाजी के लिये धन दिया जाता है उसको किसी दूसरी जगह बहुत कम लगाया है। तो इस तरह की प्रवृत्ति को सरकार को रोकना चाहिये। केवल आगरा और दिल्ली में ही आर्केलाजी के स्थान नहीं हैं, बैलोर में भी हैं, मद्रास में भी हैं, गुजरात में भी हैं, बंगाल में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं और मध्यप्रदेश में भी हैं और बहुत से दूसरे स्थानों पर हैं।

श्री शीलभद्र याजी : बिहार में सब सेज्यादा हैं। बिहार को भूल गये।

श्री निरंजन वर्मा : जी हां, बिहार में हैं, मैं मानता हूं। तो इस धन का उपयोग सब जगह होना चाहिये, मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं।

SHRI B. T. KEMPARAJ (Mysore): Madam Deputy Chairman, I support this Appropriation Bill placed by Government before this House for spending an amount of Rs. 1,60,72, 88,90,000. The proposals for expenditure placed before this House show that large amounts have been proposed to be spent on several developmental works. There is no doubt, Madam, that the Government has been spending large amounts of money for various schemes in all fields and in all walks of life of the individual in the society but the primary consideration is that the benefit of all these schemes is not felt by the individual in the society. When such large amounts are spent this is the point which has to be taken into consideration. Though crores and crores of rupees have been spent under the Five Year Plans successively in industrial, social and educational fields, the individual to whom the benefit ought to have reached and whose condition should have been improved has not felt it and that is the reason why there is hue and cry from all quarters that the Government is not giving any substantial benefit to the individual in the society. This is a very important thing which we have to bear in mind.

In the industrial field though crores and crores of rupees have been invested, when you compare with the private sector you find that in the private sector there are huge profits made while in the public sector there are huge losses. Why is it

so? The answer is very simple. The private individual takes pergonal efforts to see that his production increases and that it brings him profit but in the public sector the capital investment is much higher than what it is in the private sector. In the public sector more than one-third of the investment is diverted towards putting up buildings and installation of machinery. If you take the case of Japan, I am told there such huge amounts are never spent on construction of big buildings or on installation of machinery. That is why, Madam, after the second world war Japan has been able to regain its position in the industrial field and also in the field of commerce in the world. When we are spending so much money for economic development, for industrial development, should we not think for a while why there is such huge loss? Several Committees have been constituted to go into this matter and they have found the reasons thereof but how far have we taken up their suggestions and tried to rectify the defects that have been pointed out? The expenditure that we incur is always much more and it goes on increasing with the result that all these are added to the cost of the product when it comes out of the factory and we find ourselves unable to compete in the international markets.

Now, take the case of education. We have accepted compulsory education in the Constitution but it is not completely implemented throughout the country. The educational system is still in a lingering state without taking any definite shape. Therefore it is essential to think of a revolutionary change in our educational system forthwith so that we can overcome this problem of unemployment. Because of the type of education that we have at present there is this difficulty. What is the type of education that we have now? After graduation every youth is tempted to go hunting for a job. The education that we impart to our youth is only a scholastic type of education which is only useful to get some clerical job in some office or other and when there 16-6RSS,ND/69 is no chance of setting a job he becomes frustrated and disappointed and he is tempted to take to other activities, that is, subversive activities. Therefore the Government should think of revolutionary changes in our system of education so as to enable every youngster who gets education to get into some field of work in rural parts or elsewhere.

As far as agriculture is concerned, the great urge is there for the development of agriculture. But there have been proposals for the levy of a tax on fertilisers and pump sets. Really such a tax will hit the petty landholder very hard. If one knows about the kind of agricuhural operations gong on in the villages he will come to know how hard such a tax will hit the poor farmers and cultivators. Therefore I suggest that it is very essential to have a ceiling limit above which taxes mav be levied. There are agro-industrial fields where the Government is thinking of levying taxes. But let there be a clear mention by the Government that the tax will be levied over and above a particular ceiling limit. That is feasible and that is also acceptable but to levy tax on a farmer who has got five acres or two acres of garden land or paddv field will work very hard on him. Therefore, I suggest, before levying such taxes, agro-industrial taxes, Government should take reasonable care and caution, so that the small holder, the small agriculturist is not put to hardship.

As far as social welfare is concerned, the Government has been doing its best for the improvement of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. In Andhra Pradesh there is the Scheduled Tribes Financial Corporation. From the tribal areas, forest produce from minor forests will be collected by the tribal people and -it will be purchased by this Financial Corporation. But then the price given to them is about forty per cent less than for what it is sold in the public market. This is one of the reasons why there is a lot of trouble

[Shri B. T. Kemparaj] in the Agency areas in Andhra Pradesh. It is necessary that the Government should think of these tribal people and see that they get a fair return on the produce sold to the Scheduled Tribes Financial Corporation in Andhra Pradesh.

Again, the land problem that is facing the country has to be solved by the Government. The land problem has become so acute in the country that many of the landless labourers have been going out of their way to occupy Banjar land or land in forests or land that is available anywhere else in the country. What I want to impress is that the land problem must be attended to forthwith. As you are aware, in West Bengal, in Andhra Pradesh and in so many other States, the urge for land is there. Though the Zamindari system, the Jotdar system and other systems have been abolished, the distribution of land to the cultivators and agriculturists has not been made. The long, inordinate delay is the root cause for the coming in of so many anti-socialist parties. To curb it, ;t is high time to think of settling these landless, agricultural labourers on land. Action should be taken immediately. If not, great difficulties will have to be encountered in the near future. It is necessary that the Government should take immediate action, with care and caution, against the anti-social elements, which have ben taking to activities by inducing these landless labourers to go against the existing system of society and law and order in the country. To prevent it, it is necessary that the land problem must be taken into considerat;on verv seriously. With these suggestions, I support this Bill.

SHRTMATI SHAKUNTALA PA RANJPYE (Nominated): Madam, I have looked into some of the figures in the Appropriation Bill before us and I find that a considerable amount is allotted for public health. Although I must say that the Health Ministry is rather a neglected Ministry—it should actually get more by way of grants from the Government—looking into the different expenditure incurred on public health and especially the expenditure incurred on my pet subject, birth control, it is a sorry state that I find myself in. I find that they are spending more than is necessary. It may seem rather awkward and one might say I am mad, because I have spent half of my life in this work. Why do I say that you should spend less? It is not that you should spend less, but you should look as to how you are spending the money. I was told that the personnel in the Family Planning programme is about one lakh. I hope I am wrong. I ask the Minister to correct me if I am wrong and I shall gladly accept my mistake, but the fact is that when we think of controlling the population in the country, without more money being spent, we can obtain better results. I have been saying this for a long time, ever since I have been here, but the Government takes little notice of it. They create posts and more posts, particularly posts at the top, which do not give us any results. I have been crying myself hoarse and shouting myself blue saying that the people who should be appointed for family planning work should be those who have themselves benefited by the programme. Of course, some of those people perhaps are asked to help as motivators or some such new-fangled name. I forget it. They are searching for it in the dictionary all the time. People who have found it to their benefit, who have used different methods of birth control, should be siven jobs, temporary jobs if you like, to do this work. From my own personal experience I have said several times in this House, simple people from the masses, who cannot write properly, who can perhaps just read, who do not speak any language, any regional language correctly, but who speak the "Dehati" language and if they are people who have improved the cond'tions of the country and of their children by practising birth control or family planning, let me tell you, Madam, and let me tell the whole House, their word has a grea-I ter weight than all the words of all

of us. I have taken these people along with me for six or seven years in Maharashtra particularly and even in Northern India. I have nothing to do. I take them with me. I give my usual urbane talk for about five or ten minutes and then I let these people loose, a man who has undergone sterilisation, an agricultural labourer or a mill hand or one who is a Hamal or a cooly or anything else, or a woman from the same area who has undergone tubectomv or sterilisation. Once these people are let loose amongst the masses and they tell their own simple stories, it has a good effect. These stories have been published and distributed by me ad nauseam as case histories. If these people were appointed and given jobs, that would give us miraculous results. Instead of it, what we do is to appoint some other people. We appoint people and send them for training in different institutions. We require them to be matriculates or have some such educational qualification. We do not see whether they are the right people to do this work, whether they can talk the language of the masses. I am very sorry and I am ashamed to say about us urban people that there is such a wide gulf between us and the masses that, I think, we are nearer to Americans, we are nearer to the Russians, than to our own people, which is a crying shame. Considering that such is the case, let us find the people from amongst the masses who can do the job themselves. Why the Government is not appointing such people I do not understand. I have been crying myself hoarse. More jobs have been created, more secretaries, more extension educators and more field workers have been appointed. My God, I cannot even think of the titles that are given to these people. But they can be found among the simple people, the beneficiaries of the familv planning work. They have done so in Maharashtra. Maharashtra has taken a good step. Maharashtra did a very wise thing in abolishing all these different posts in the Family Planning Department. They did a little too much of it, I must say. They have appointed one coordinator per centre which again is not enough. There were about six before instead of which they have appointed one. They have said that the expenditure was too much. But they have appointed motivators to do the work for sterilisation, operation, etc. A lot of malpractices have taken place. These motivators are given Rs. 10 for their out of pocket expenses. But if they had appointed, as I had suggested, people who had benefited by the scheme, given them temporary pay and, perhaps for every case they bring in for sterilisation, given them something else in addition and given a job security for about twelve months or two years, I think they would have done work more satisfactorily. They wou d have been answerable, responsible for their work and all these evils that we read about in the papers of young boys of 18 and of old men of eightv being sterilised would never have come about.

Another point I have been raising is that of disincentives. I have been reading this report on the small family norm and I am glad to see that they have made some very wise recommendations. I do not agree with all the recommendations but I do think that quite a number of them need to be adopted and implemented. But, Madam, Government is only going to consider it. Consideration takes a long time. I do not know when this report will come before the House. It will take years perhaps. After those years, another few vears will be taken to consider, to implement, and so on. Bv that time we will be 60 crores or 70 crores or 80 crores. There are simple methods that can be introduced. Stop all increments, all promotions, all kinds of facilities to people who are recalcitrant towards accepting the scheme of family planning. I do not sav that we should be harsh on them. Give them ample notice that we do not want more than three children in anv family. "If you want more children, you have to pay for them. We cannot give you any amenities;

[Shrimati Shakuntala Paranjpye]

we cannot give you any facilities; we cannot give you any help; go ahead if you want them". I do not say that they should be forcibly stopped. But if people will not see the good to the nation and the good to their own family by controlling the size of their family, I think those families should be made to pay for it. Disincentives, I think, would go a long way. I have tried it mvself. Madam, how many more minutes I have?

THE DEPUTY CHAIRMAN: You can have five minutes.

SHRIMATI SHAKUNTALA PARANJPYE: I have done it in my own little way. When my father was a Minister, he had built a house with servants quarters and all that. Afterwards when he ceased to be a Minister or hold any official position, of course these servants quarters were unnecessary. But my father is one of those who would not rent it out. So all these rooms were empty. Seeing how frantically people were trying to find accommodation to live in, I could not bear it, and I used to offer it, free of rent of course, to whoever wanted to come and stay and keep the place clean and keep the size of the family within limits. A family came and stayed. There were no children. Then one child arrived. Then the second child arrived. After that I told the people, "My good friends, I do not want a third child, or perhaps a third but not more than three". So the third child arrived, and I said, "Now I will not have any more; otherwise you will have to leave the place". However as it happened, the woman went to her mother-in-law as she was very ill and she had to go to look after her. Before going of course I had given her all the necessary appliances and so on and sent her to her mother-in-law. But she stayed there for a year or more than a year. When another brother-in-law of hers got married and there was another woman to look after the mother-in-law, she came back to our house. I enquired as to where she was. She would not come before me. So I went to her room myself- I went into the room. She turned her back; she would not face me. I turned her myself. I saw she was ready with a fourth child. I said, "What has happened? I had given you the appliances." She said, "I ran out of those". I said, "You should have written to me, Bhagi". She said, "Madam, how can I? I cannot write". I said, "You should have asked somebody else to write". She said, "How can I ask somebody else about such a thing?" I said, "You are perfectly right. It is my fault for not having seen through your problem. Anyway this will be a full-stop". She said, "Certainly. My husband is undergoing operation". She had known about the work I did, and the operation took place. That is how in my little home 1 had used these practical methods to see that people—as you know, they could not read or write—could understand the benefits of the scheme. After a while the family had left this room in my father's house because they got better quarters in the Police headquarters, because they were police people. Several people were wanting that room and they came to me. Before accepting new people on the premises one alwavs feels reluctant and hesitant. I said, "You are a taxi driver: vou have a car: vou want to use my garage: vou will be using the water, and leaving everything in a mess". They promised to do everything as I wanted. Still I was holding back. The last 'astra', the last point that they made was, "Madam, you will have to give us the room because my wife underwent sterilisation operation". That was the passport to find accommodation in these outhouses.

In mv little wav I have shown many people how it can be done and if one keeps an eve. on it whatever vou do. whether it is any help or am thing, if you introduce this spirit of disincentives. I think vou will get excellent results. I have alwavs stressed two points; getting the help of people, who have benefited by the programme, from amongst the masses

and using the principle of disincentives to recalcitrant people. Thank you.

SHRI N. PATRA (Orissa): Madam, I support this Appropriation Bill this year, but while doing so I will refer to some of the unproductive features of this Bill. Against an appropriation of Rs. 16072,88,90,000 from the Consolidated Fund of India for the service of the debts a sum of Rs. 1,00,10,11,06,000 is needed. Not only that. As interest for the service of these huge debts another amount of Rs. 568,86,07,000 is needed. Besides this, another unproductive feature of this Bill is that we have to pay towards the privy purses a sum of Rs. 4,80,66,000. Altogether it comes to a huge amount of Rs. 10583, 77,79,000. What is left for the developmental expenditure of this vast sub-continent? Only Rs. 5489,11,11, 600. What is the percentage? It boils down to 32 per cent. But even this 32 per cent is not left entirely to development. Sixtyeight per cent has to go into unproductive expenditure, to pay for debt charges, debt servicing and for the Maharajas towards their privy purses. We are barely left with 32 per cent. Even out of this 32 per cent, half or more than half goes towards administrative expenditure. What is left then? Only 15 to 20 per cent is left. This is for the socialistic pattern of society, to uplift the poorer classes of the population. It is very difficult to achieve this. Somebody was very liberal in giving us loans and we were jubilant to take the loans. But the consequence is that nothing is left for our developmental expenditure. This needs to be noted.

The only sector which is coming to the aid of the Central Finance Minister in a big way is the agricultural sector. We were giving so many subsidies in order to encourage more production. The kisans rose to the occasion and wanted to help the Government and also the country. By toiling most they have earned a few paise. But what is the Government now doing? Government withdrew all those subsidies which they were giving till last year. They want to mop up some of their income which they have earned by keeping the revolution green in the fields. They want about Rs. 22 crores from this sector. This morning, while replying to a question, the hon. Finance Minister was telling the House that about Rs. 84 crores by way of income-tax are not paid by the industrialists. In spite of this huge evasion of Rs. 84 crores of tax money which is to be paid into the coffers of the State, these people were given the most favourable consideration; they have been given so many concessions to revive the industrial growth of the country. You know that the developmental growth of this country depends upon agriculture. You want to kill this hen which lays golden eggs. Then how can you have even an ordinary egg? They are killing the initiative of these people who are toiling most, and the Government has a hope also of doing away with PL-480. From what other section could they get the green hope excepting this agriculturist class, the rural sector? With their help, they want to augment the resources of the country and to develop it most rapidly. But they have thought it fit to hit at agricultural production by taxing fertilisers. I think they are most ill-advised in this respect.

At the recent annual session of the Congress, our revered President, Mr. Nijalingappa, wanted that the public sector undertakings should hereafter give us returns. But there was some criticism also when he said that. We are very enthusiastic about the public sector. I stand for the public sector in a big way. It is a mixed economy. I am not against the public sector. But sometimes we should be able to manage our own affairs in a better way. Instead of getting anv return, we are losing about Rs. 35 crores annually. This big loss has to be made good. Therefore, in the management of these public sector undertakings, people not only with administrative calibre but also knowing better management and commercial practices have to be inducted.

[Shri N. Patra]

While supporting this Bill, I want to draw the attention of the hon. Minister to a few wants of my own State, Orissa. Orissa is full of resources. There is the deepest seaport of the eastern region, which is called the Paradeep Port. That port was built by the initiative of a single man, Shri Bijoyanand Patnaik. He is no longer there in power. But it is a great achievement not only to his credit, but also to the State. But what is the Centre doing after taking it over? The experts in the Ministry of Shipping have given the green signal that a second general cargo berth has to be built there. But to our surprise and dismay, we find that no provision has been made for it in the Fourth Five Year Plan.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THE NGARI) in the Chair]

In this connection the proposal to link the port with the Rourkela project having a belt of about 400 sq. miles of mines and metals has been examined at every stage. The Bimla-' garh railway project does not get any mention in the Fourth Plan Draft. About the development of that port the Government has to take steps and find money; otherwise the present Opposition Government would mislead the masses against the Congress Government at the Centre. You might have seen in the papers today the statement of a P.S.P. Member that since there is an Opposition party Government in Orissa, the Congress Government at the Centre would put them into difficulties and immediate development activities in the State would receive step-motherly treatment. I hope the hon'ble Minister would not allow this criticism to be made and he would see to it that due consideration is given to the developmental projects of Orissa. With these words I support the Appropriation Bill.

SHRI M. RUTHNASWAMY (Tamil Nadu): Mr. Vice-Chairman, the Appropriation Bill No. 3 gives us an opportunity to review the working of all the Ministries during the past year. I shall not be able to touch all the Ministries that can come under review. I will just select the most important of them, the Ministry of Defence.

Sir, one of the most brilliant utterances that came from the lips of any Prime Minister in India was that made by the present Prime Minister some time ago when she said that we used to think the Himalayas would defend us but now we have to defend the Himalayas. In other words, we looked upon the Himalayas as an impenetrable barrier through which no invader could come and threaten us, but the Chinese invasion showed how it was possible to breach the Himalayas and invade the country. It was a wise and frequent utterance. But may I know whether the implications and corollaries of these utterances have been followed up by the Ministry of Defence?

They speak of self-sufficiency, making India depend upon itself for the purpose of Defence. They have an Army of 8,25,000 men, an Air Force of 45 squadrons which has about 500 units and a Navy which consists of one aircraft carrier, two cruisers, two destroyer squadrons and a few other types of ships. With this Force, would India be able to defend itself on two fronts? In fact, there are three or four fronts because the Pakistan front extends all over the border in the North-West and links up with the Chinese menace in Ladakh.

On the other side, that is, the North-East Frontier, we have China to deal with; we could take Pakistan by itself, but Pakistan and China combined would be a terrific combination. It is true that the Navy is doing much. It is adding one modern Frigate per year with anti-submarine equipment, and it has, as I said, one aircraft carrier and it hopes to have one submarine a vear. But, with this equipment, would anvone dare to say that the naval defence of India is adequate?

Only yesterday the newspapers published a summary of the conclusions of a study group of the Naval Department in which, after analysing the various Naval resources open to us, it has come to the conclusion that the Naval defence of India by India itself would be utterly impossible to meet the menace from the seas and they came to the daring conclusion, which we on this side hinted soon after the Chinese invasion, that India should take the initiative in organising a South-East defence alliance to meet the menace on the east. I am glad to find that an expert group like this study group of the Navy has come to the same conclusion that India as a South-East Asian power is almost a Pacific power and it must take the initiative or at least join in the organisation of-South-East defence which would include both Japan and Australia.

Sir, if the utterance of the Prime Minister means anything that the Himalayas are no longer a defence of India, the Government of India, especially the Ministry of Defence, should follow that principle to its natural military and naval conclusion that we must be able to organise the defence of India on a co-operative basis.

It is good no doubt that we are adding these frigates and submarines but there is what Mr. Winston Churchill called during the war a "Mosquito Navy" which saved England from invasion by the Germans soon after the fall of Dunkirk. A number of small vessels, gun-boats, landing craft, mine layers, mine-sweepers are necessary to defend the long sea-coast of India. The Defence Ministry report says that we have a couple of mine-sweepers. But what is more necessary for the defence of our sea-coast is a couple of mine-layers, specific mine-layers or ships equipped with mine-laying equipment. One Naval dockyard at Mazagaon is not enough. From the visit that I paid to the Mazagon Dockyard, I found it rather congested. We should have more than one dockyard. Goa offers a very fine site for another naval dockyard, and on the east coast, not only Vizag but other ports should be surveyed in order to find whether they can offer a site and opportunities for the building of naval dockyards.

As regards army itself, it is not so much the conventional army that is going to defend India because China under Mao Tse-tung has initiated an era of guerilla warfare, small groups of soldiers, two or three, going about and creating trouble either attacking or defending. That is the kind of training that our troops require-gue-rilla training. Officers and men should be trained to depend upon themselves, depend on their own initiative, on their own individual resources, on the resources of the locality in order to find their way about on the border and be equipped with small arms to be able to defend themselves or defend their locality and to attack the enemy. The success of the army or the success of the defence service depends much on the intelligence by which it is served. Both the Chinese war and the Pakistani war have shown that our intelligence is very weak, not highly developed, not well equipped. There is a book, recently published, which speaks of intelligence at the top. It is not intelligence in the usual sense, namely, cleverness. It is the ability to get information to find out what the enemy is going to do, is about to do. And fpr that we want a well-trained intelligence unit in the army. We hope that this intelligence unit will be well developed because it is on the work of the intelligence service in the navy, army and air force that the success of our defence forces and our preparedness for any attack on any front will depend.

Then I come to the Ministry of External Affairs. At last we have a Minister for External Affairs—and not the Prime Minister doing also the job of the External Affairs Minister in leisure moments. I am glad to find that in answer to one or two questions, the new External Affairs Minister spoke of national interest as being the determining factor in the

[Shri M. Ruthnaswamy] shaping of our foreign policy. Although it may be necessary or it may be the habit of our External Affairs Ministers and the External Affairs Ministry to repeat the manthra of non-alignment, in fact, they ought to pursue a positive policy. Recent events have shown that India; like Pakistan, has actually come into the Russian sphere of influence. The Tashkent Agreement was entered into under the auspices of the Russian Government and this Russian sphere of influence in Asia which Russia has been after for the past 100 years has at last come to take shape. But if one is within the sphere of influence, if one has walked into the spider's parlour, it may be difficult to get out, but it may be possible to stay where we are, not to get deeper into the Russian sphere of influence. A clever external affairs policy would be to play Russia and China against each other, play off one against the other. But that requires cleverness, that requires caution, that requires foresight also. But in order to do that, in order to keep independent of both Russia and China and of every other power, it is not necessary to know Kowtow the Russians as the Minister of External Affairs did the other day when he went out of his way to support Russia in its conflict with China. Was it necessary? Are we adding to the strength of Russia by going out of our way to proclaim ourselves on the side of Russia as against China? It is in your interest to let them collide with each other, let them fight each other, so that they might divert their attention from us. In order to have an independent foreign policy it is necessary to keep ourselves aloof. You speak of non-alignment. Is this non-alignment—going and supporting Russia in its struggle against China? Why can't you keep quiet? Why can't you keep your mouth shut? Has any one asked you to go out of your way to support Russia?

SHRI AKBAR ALI KHAN: Do you put China and Russia on the same level?

SHRI M. RUTHNASWAMY: Yes, from our point of view they are on the same level. Both are enemies; the one actual, the other potential, both want to have influence over us.

I was glad to see that the new Minister of External Affairs laid stress upon developing the economic role of our foreign missions. If we cannot develop our international influence, at least let us develop our foreign trade. And in this our missions can play a useful part. We have the commercial attaches attached almost to every mission. What are they doing? Are they sending us their reports from month to month? I put a question the other day to the External Affairs Minister whether these periodical reports of our commercial attaches were published. He said "Yes." But when I went and enquired in the library, I found that there were only publications containing t^ie decisions of the Government on the reports received from the trade commissioners or the commercial attaches. What we want to know, what public opinion wants to know, is actually the reports of our commercial attaches, of our trade commissioners, to see what they are doing what can be done here in India for the development or expansion of our trade.

Turning to the Ministry of Home Affairs, we find that recent events have shown that our police force is utterly inadequate to deal with the problems of to-day. This police force in its numbers, in its equipment, in its organisation, was good enough for the old days when we did not hear of riots, of daily riots, of gheraos, handhs, strikes and of all kinds of violence and disorder. The 250,000 strong police force in our country is utterly inadequate to deal with the problems the police has to deal with to-day. We have to live with riots at the present time. They are part of our daily life, and for that, a special riot police as has been organised in France and in the United States of America, ought to be established in this country—a special force for

every kind of development of trouble. We have already an Industrial Security Force. On the Railways, you must have your own Railway Police Force, not the inadequate Protection Force that you have. We want a force that will be able to patrol the whole lines with its own equipment, with its own motor bicycles, with its own radio equipment and so on, which will be able to patrol the lines day and night. That is the only way of dealing with sabotage. Even countries which do not have to deal with sabotage like England have a special Railway Police.

Then I come to the Ministry of Education. Although Education is a State subject, it is a national responsibility. Education is a major responsibility of the Central Government which is charged with the duty of developing the moral and material welfare of the people. In a federal country like the United States, there is a Department of Education and National Welfare. But this is a real Department of Education because it helps the States to supplement their educational efforts, to supplement their educational budgets. Large sums of money are being given bv the Federal Government of the United States of America in order to develop vocational education, technical, agricultural education. Here literacy is our fundamental problem. Everyone, the people and the Government, ought to be ashamed of the state of illiteracy in our country. Eighty per cent of our people are illiterate. How can any Government be satisfied with such a state of affairs? The States are not doing enough. It is, therefore, the dutv, the responsibility, of the Central Government to pump aid into the States so that they can make literacy develop at a much faster rate. At the rate we are going, it will take 75 years for India to become totally literate. It is developing at the rate of 1 per cent per year. Adult illiteracy is a great problem. We cannot wait till all our boys and girls become literate. The present adult population must be made literate in order to be of any use to the country, political or economic use.

Then there is the Ministry of Transport and Shipping. It has not only to do with the international shipping and international transport. It has to do also with the internal transport. Only the other day the former Minister of Transport said that we must give high priority to village roads. But what is the Government of India doing for the development of village roads? The Committee on Roads, the Sinha Committee, recommended that India should spend at least Rs. 75 crores per year for the development of our roads, especially of village roads. What is the amount of Rs. 75 crores a year spread among fifteen States, Rs. 5 crores per State? It is absolutely necessary that we should develop our rural roads. It is very necessary for the development of our economy. Agriculture cannot flourish unless there is a rural road connecting the farm and the village with the nearest town, with the trunk road which would allow the farmer to go and sell his produce at the best price possible at the nearest market whereas now without village roads these farmers are at the mercy of the middleman who buys the produce not to the peasant's advantage but to his own advantage. Here again the United States of America sets an example. There in the Federal Government there is a regular Bureau of Roads which has to deal not only with the development of highways or big trunk roads, but also with the development of rural roads. And such a bureau is necessary also at the Central Ministry of Transport and Shipping here.

Then there is the coastal trade which is neglected. We have 3000 miles of coast. We have about 250 minor ports. Everyone knows that waterway traffic is much cheaper, especially for bulk goods, bulk cargo, than the railway or even the road traffic. There ous;ht to be a busy coastal traffic between all minor ports and major ports. Our ports must be

[Shri M. Ruthnaswamy] bristling with activity whereas now they are as dull as ditch-water. While Rs. 75 crores have been spent on the development of major ports only Rs. 11 crores have been spent on the development of minor ports, and the belief is that minor ports are the primary and principal concern of the States.

And then, of course, we have the Ministry of Family Planning. Hundreds of crores are to be spent on family planning. And what is the result? In twenty years, I believe, the population has been reduced by two millions—a reduction of two millions in a population of 500 millions. Is it worth considering? Is all this the effect, the consequence, of all your activity in the field of familv planning? If this amount of Rs. 100 cropes had been spent upon the education of our youth, upon the education specially of girls, if some of these hundred crores had been spent on rural housing, that would have done much for the limitation of our population. In every country education and housing have been with of course, economic development, especially industrial development, the means of limiting the population. Raise the age of marriage and thereby improve the quality of your population. Improving the quality will ipso facto bring down the numbers of vour population.

And finally, Mr. Vice-Chairman, there is our inaffable Administrative Reforms Commission. It was started in 1966 and it is still going its merry way year after year. We are now, 1 think, in the third year and we do not see the end of it yet. It has published about six reports and, I believe, it is going to publish four or five more in the course of this year. The Administrative Reform-Commission, which costs about Rs. H lakhs a vear, looks like a vested interest. It looks as if it wants to perpetuate itself. But what has this Administrative Reforms Commission done to solve the great problem of the cost of administration? Our Government is not cost-conscious. Money is nothing to them. Money is no consideration to them whereas every Government worth the name ought to be cost-conscious. What is our Administration costing us? Is the cost worthwhile? People have compared our Administrative Reforms Commission with the great Hoover Commission of the United States of America. There is no point of comparison at all.- This Commission is a parliamentary commission composed purely of Members of Parliament, busy Members of Parliament, and composed mostlv of socialist Members of the Congress who are ruling whereas the Hoover Commission was an expert commission, composed of public men, one or two business men officials, administrators. And it produced a report which reduced the cost of administration by some billions of dollars. We have yet to see a report on the cost of administration produced by our Administrative Reforms Commission. And if it does not do that, then, we need not have appointed the Administrative Reforms Commission at all.

SHRI G. A. APPAN (Tamil Nadu): Sir, on a point of information and clarification. I really wonder if the learned Professor has gone into the various reports that have been published by the Administrative Reforms Commission. For his information and for the information of the Government I may also say, Sir, that all the reports that have been submitted by the Administrative Reforms Commission have been of vital importance to the nation. They have published very very useful information and they have naturally saved the administrative costs also to a great extent and...

SHRI M. RUTHNASWAMY: What is the extent of economy effected?

SHRI G. A. APPAN: Of course, it is a thing which has to be worked out. But it cannot be gainsaid in such a rash way that they have not done any useful work.

SHRI M. RUTHNASWAMY: We want a special enquiry into the costs. I had not said that they had • not done any useful work at all. But they would have done more useful work if they had gone into the question of the cost of administration because money is vital to any system of administration. What is the use of having an elaborate administration which costs the tax-payer an immense amount of money and which does not produce results in keeping with the cost of administration? Therefore, unless the Administrative Reforms Commission goes into this question, this specific question of the cost of administration, and shows how the costs can be reduced by so many millions of rupees, by so many crores of rupees, I think in spite of the advocacy of the honourable Member on the other side, the Administrative Reforms Commission will not have served any useful purpose at all.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, while speaking on the Appropriation Bill I would like to draw the attention of the Government to a very vital problem, the unemployment problem in this country, and the failure of the Government to tackle this problem in right earnest, and particularly the enunciation of the financial policy by the Government in the Ministry of Finance.

Perhaps you are aware that in this House we have discussed this so many times. When Dr. Sen was in charge of the Education Ministry, he also announced some policy to employ the educated graduates in this country.

SHRI AKBAR ALI KHAN: Technical graduates.

SHRI A. G. KULKARNI: Yes, I am particularly more distressed that when such policies were announced, actually the financial infra-structure required to be created for these policies to go through has failed. I am surprised that the Government has not realised what is the danger par ticularly when we say that the technocrats are finding themselves very much frustrated. I am not wild enough to advise them: 'Let them look to France or any other country where these students have led such revolutions which have toppled the Government'. In this connection I want to put the record straight and put before the Government how their policy particularly towards the small industries is failing and if only they have been nourished properly the small-scale sector, these problems would not have arisen. We have been hearing time and again about the appointment of the Credit Council and Social control on banks. It is also true that in this House I had particularly drawn the attention of the Government to the very inadequate credit even after the appointment of the Credit Council but 1 am prepared to give them a further one year and even if they ask for two years, I do not mind it but I would Hke to know what is the matter regarding the small industries and why the technocrats are finding it very difficult to get encouragement. That must be studied and there is also a financial angle to it; otherwise, the responsibility cannot be fixed. In this country we have a mixed economv and there is a small industry as well as the large-scale industry living together and the Government has so many times trumpeted all through the plan periods that there is the 1956 Industrial Policy Resolution. You will see that the total bank credit available to the small industries is less than 4 per cent, of the total credit available to the organised industries in the country and 66 per cent. of the total credit is made available to the large and medium scale industries. This is the present position of credit available through the commercial banks and the financial banks and institutions of the Government. If you look at the relative contribution to the national income, the organised big and medium industries contributed 7 per cent, as against 7.6 per cent, by all the small industries put together. Looking to

[Shri A. G. Kulkarni] the contribution to the national income also, you will find the vitality of the small-scale industries. If you fake another figure, you will find that the fixed capital required for employment in the small industries is about Rs. 1800 as against Rs. 17,000 in the large-scale sector and the value per unit of investment is 1.22 in the <mall sector as against merely -35 in the large-scale sector. I have no aversion to the larger industries. They are the basic industries but why I say this is, the Government has particularly failed in implementing the Industrial Policy Resolution. They have failed in understanding the problems of the educated unemployed and they have also failed to understand the world position as regards the vitality of the small-scale industries and why the various world Governments are supporting and going out of their way to help the <mall industries. Here in this country our entire pattern of thinking is, iajst like the late President said: 'Only talk give lectures and do nothing and the least Government an do is not to implement anything'. If you take for the year 1968, the fotal production of the small-scale sector was about Rs. 2800 crores a vear which amounted to 30 per cent, of the total industrial production in this country and if the unorganised industry is taken together, it is 50 per cent, of the total industrial production in the country. 1 may also state that 90 per cent, of the total registered factories in the small-scale sector gives employment to 40 per cent, of the total employed in factories in the country. These are the good points and what have our Government done during the last three Plans to the small-scale sector? They talk of democratic socialism, socialistic pattern of society, decentralised sector and they give lectures. The Ministers and the Government vie with each other and say they are helping the small-scale industries but what is that help in the Plans? The actual help must come through the financial help provided for the development of the small-scale sector. You will be surprised that in the First Plan only 1.3 per cent, of total plan funds was provided to the small scale sector as against 12 per cent, for the large-scale industries. In the second Plan it was 4 per cent, as against 22 per cent. In the Third Plan it is less than 4 per cent, as against 28 per cent. Why I say this is, the Fourth Plan is coming. They have provided Rs. 295 crores as against Rs. 10,000 crores for the entire industrial sector in this country. The Government on the one hand supports in theory the small-scale sector, and talks of principles very loudly, and talks of help to the small-scale sector to find out ways and means of helping the educated unemployed, when it comes to actually practising it and doing justice to these things, they have not done any thing and if they had done one-hundredth of what they promised, the problem would have been solved. What does the Industrial Policy Resolution say:

"The aim of the State Policy will be to ensure that the decentralised sector acquires sufficient vitality to be self-supporting and its development is integrated with that of the large-scale sector."

This is the pious wish of the Government, as mentioned in the 1956 Resolution regarding the position of the small-scale sector vis-a-vis the large-scale sector. I have given the figures and anybody will be convinced about the strong points in supporting the small-scale sector. I have indicated to you how the Government is behaving and I have stated about the credit position and what per cent-age they are giving. In this House we have debated that well-cursed Resolution on the Birla Enquiry because we have spent more time without getting any tangible social gain. The large-scale industrial sector which is aggrandising about 66 per cent, of the credit, what is the rate of interest they are paying actually? In the last session, when Mr. Sethi's predecessor Mr. Pant was there, he was very much interested when I disclosed that the small-scale sector received credit not below 12 per cent, anywhere in

the commercial sector. I know the State Bank of India has announced certain rates which are well below what I say but the State Bank is not giving credit to the entire small-scale sector in the country. It is not even serving 10 per cent, of the entire small-scale sector. It is only the commercial banks that do. Mr. Pant was good enough to have a dialogue with me and some correspondence with me. In my own wisdom, I also addressed various letters to the various banks because I attended a banking seminar organised by the Industrial Development Ministry and the Development Commissioner. There were various bankers and some of their chairmen were very much annoyed at my disclosure that they are charging fabulous rates of interest from the small-scale industries and that all the talk about social control of banks is all humbug, and that the agent at the lower level in the village or small town is not prepared to do justice to the small and medium industries. The entire paper goes to the Head Office and then some decision is taken after 6 months or a year. Now Mr. Sethi must accept my challenge to his Ministry and he has to accept my claim that the small-scale industries are not done justice in the matter of credit at cheap rates as the Government thinks. Having seen all its good points as regards providing employment, as regards its contribution to the national income and as regards its total production in this country, what right this Government has to charge this small-scale sector a 12 per cent interest rate as against the 8 per cent rate charged to the large-scale sector? Mr. Vice-Chairman, please look at this staggering figure; about Rs. 1800 crores are supposed to have been given—as per the Monopolies Commission—to the undertakings in the large-scale sector; at an interest rate of between 8 and 8.5 per cent they are getting all this credit; there might be 6.5 per cent for pledged credit. As against that, the small-scale sector—barring the State Bank of India which is advancing credit to it at a lesser rate of interest—is getting all its credits at a rate of interest of between 9 and 12 per cent. Now I have addressed letters to them, and have got their replies—I have got that, what you call, album with me—wherein so many agents of well known banks have confirmed my information that they charge 9 to 12 per cent interest. The interest goes on accruing to the account and at the end of every three months it is added up to the principal and the amount obtained this way becomes the principal for the next quarter. This way the interest rate works out to 15 per cent and more, as against the 8 per cent interest charged to the large-scale sector. I do not want to blame the monopolists. I do not want to abuse them or curse them at all. But what I want to say is that a small man, a small entrepreneur doing business himself, is charged between 9 and 15 per cent as interest charges. So is there any justification for this Government \o talk of socialism again in this House? I do not find any justification at all. Mr. Vice-Chairman, why I am saying all this with so much agony in my heart is because I am trying to say that the small industries in this country must, at least for credit purposes, be equated with the big industries, more because you want the technologically educated people to start industries. You want them to be entrepreneurs. Now, first of all they have had no upbringing in the industry; they are to try, make mistakes and then acquire some knowledge. And for that purpose what incentives you are going to give to them? If nothing else, at least give them liberal credits. Charge them a rate of interest commensurate with the risk they are going to undertake. Otherwise, all this tall talk of a social revolution is a faked talk, and it does not become Government to talk like this. Mr. Vice-Chairman, why I am saying this thing is also because of this, of what we see in Japan. Now Japan is an advanced country. I do not want to make detailed comparisons between our country and those other countries like Japan which have glories to their credit because they are not going to make

[Shri A. G. Kulkarni] any impact on the Government, I know; I am very sorry to say that. But let me say this. To Japan so many Ministers and so many officers of the Government of India have gone and come back. In Japan there are large-scale industries. Japan as a nation is an aggressive exporter and Japan exports like anything. What lessons we have taken from them? Only we have passed this Industrial Policy Resolution, and in this new Plan also I was trying to find out whether the learned economists now adorning the Planning Commission, whether they have gone deep into the maladies of the small-scale sector. I tried to find out whether they have made any structural changes for the Government to make a change in their approach to the small-scale industries. But, Mr. Vice-Chairman, I am sorry to say that they have again just piously stressed the importance of the same old Industrial Policy Resolution in English and explained it and their approach to it which in sum amounts to the same old approach hitherto made by the Government. Now the English language is a very funny thing; it is not for poor people to understand it, understand what they really mean. It has got so many cliches. But what do they mean in the ultimate? It speaks of good things—of modernisation and improvement, and of all the other things, to help this man and to help that man.

SHRI ARJUN ARORA (Uttar Pradesh): It is just streamlining.

SHRI A. G. KULKARNI: Some such golmal goes on all the time. And again what is the infiltrate here? I am a science student; what is the infiltrate? It is the concentrate down below, and here it is zero. It is all ash, nothing else. All is exhausted out while only concentration takes place. Now what I want to say is this. In Japan, the basic law of Japan is the basic small enterprise law. Of course in Japan there are the big industries; why say only big industries, there are huge industries, but then the small-scale sector in Japan is as vital as the large-scale sector. It is meant to help the small men to set up the small-scale industries. They are of an ancillary nature, a link between the small men and the big men running small-scale industries and large-scale industries respectively, the small supplying the needs of the large. The modernisation of a small machine is also looked into there by the Government through the agency of, what you may call, municipalities. They have got a different approach towards all these things. Mr. Vice-Chairman, why I am saying all these things is because of this. Now you want these educated people to enter aggressively into the field of industry, but then, unless you follow the same pattern as is in evidence in Japan, there is no hope for them and for the country's all-round development, and all this hope will be just a pious hope. That is why I am saying all this. Now, Mr. Vice-Chairman, we have the Ministry of Petroleum and Chemicals and a vast new field has been thrown open to them because, out of the educated unemployed technocrats, 60 per cent are science graduates. If only Dr. Triguna Sen, the Minister, is given sufficient funds, a lot can be done for them and the country's development. We have more and more oilfields coming up, in Assam, in Gujarat, and so on. Now, as you know, Sir, this country has been brought on the oil map of the world. We are proceeding apace with oil technology and other types of technology and a vast field has been thrown open by the technologists. What I want to say is this. The field is there. The material is there. But the wish of the Governmeni is so much circumscribed and is inhibited by controls and this thinking and that thinking and all the rest of it that, ultimately it does not help the small man to start an industry which will be beneficial for this country. Mr. Vice-Chairman, while dealing with this problem, what I want to say is that all your approach must be production-oriented and I must say particularly that you must offer easy terms of credit to the small entrepreneurs. Much could also be

said on the supply of raw materials to the small-scale industries, but I do not want to repeat what I have often said in this regard. I have said so many times how meagre is the supply of raw materials to the small-scale industries. If you really want the technologically-trained people to enter into the small-scale industry, you must accord them training facilities, easy credit facilities and also the supply of sufficient raw materials. And in the industrial estates where such industries are set up, the infra-structure must be there, power must be available there and everything should be ready at hand. But that is not the case and I have this to say about three or four educated people whom I tried to rehabilitate in my industrial estate at Sangli. Ultimately they came to me and said, "Mr. Kul-karni, we are sorry—such is our expe-rience—we are interested in service but not in industry." Why? they told me that their difficulty was because of the control on power, the control on capital, and because of so many other guarantees required by the Government because they come into the picture. So they said, "We do not want that industry. Let us serve somewhere and be happy with what we get, free from all sorts of this kind of difficulties in industry." Such an atmosphere is not congenial to the small entrepreneurs and it should not be the case when in this country we want to make big strides in industrialisation and we want to reach the take-off stage in industrialisation. And if we really want to reach the take-off stage, Government must do away with that type of thinking which is inhibiting production, and that is why, Mr. Vice-Chairman, I again plead that at least Mr. Sethi should give me some relief in the rate of interest charged to the small-scale sector, and if I achieve that much relief at least by this speech, I should be too happy.

SHRI ARJUN ARORA: That at least he must do.

SHRI A. G. KULKARNI: Mr. Vice-Chairman, I have got with me, as I said earlier, ten or fifteen replies received by me from the banks—they are all big banks—wherein they say that it is a fact that the interest rate charged to the small-scale sector is between 9 and 15 per cent, that it is only 9 to 12 per cent but because of the compound nature of the interest it goes up to 15 per cent. Mr. Vice-Chairman, this is how these people are treated as against the favoured treatment meted out to the big sec-tor. That is why, Mr. Vice-Chairman, I again plead that some reasonableness must dawn on this Government and at least they should come to the help of the small man.

Thank you, Mr. Vice-Chairman.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA (Mysore): Mr. Vice-Chairman, Sir, I oppose this financial Appropriation Bill which provides for such vast sums of money to be appropriated by different Ministries during the current year. I would have supported it if all the spending which has gone on all these years had resulted in the economic regeneration of this country. But our experience has been a rather sorry one. In the first two Plans there was very great stress on industry to the neglect of agriculture. And, when the industries were trying to pull up, then again the usual additional tax burden came in, and we have been seeing recession in all the industries. Now take for example the textile industry, see its fate even now, and then take the engineer-ing industry and see the recession that overtook it. Later on, because of the food shortage and the enormous sums of money which had to be utilised for the import of foodgrains, suddenly a decision was taken that there should be more effort at greater food production and that for achieving that there should be more inputs into agriculture—that was the accent on agriculture. And then, when it is just making a little progress, we talk of a green revolution—I do not know where that green revolution is. And then taxes are coming round every agricultural input, tax on

[Shri U. K. Lakshmana Gowda]

pump-sets, tax on fertilizers and, added to it, tax on agricultural wealth. This type of erratic planning and policies of the Government have done justice neither to the industry nor agriculture.

Coming from plantations I would like to limit myself to comments on the plantation industry which is a specialised agriculture in this country. I find that during the past several years in spite of the fact that these traditional exports from plantations have been doing their best for the foreign exchange earnings of this country enough attention is not being paid to this plantation industry at all. We find there are heavy export and excise duties. It is really something strange that in the case of tea in addition to the export duty there is excise duty. These levies have increased export prices and reduced our capacity for competition in world markets and we all know how the tea industry has been suffering and losing its place to other tea exporting countries like Ceylon, Kenya and others. The same is the case with regard to coffee but because of shortfall in world coffee production the coffee prices are maintained for the past few years. It is not as a result of Government policies but as a result of world position that our coffee is maintaining its place in world market.

We find with the present imposts on fertilisers and pump sets and Other direct and indirect taxes on agriculture the cost of production of these exportable plantation products has gone up and that has further lessened our competitive position in the world markets. We all know that realising the difficulties which were faced particularly by the tea industry the Finance Ministry thought of giving some relief in the export duty leviable on tea but that has been offset by the increase in the cost of the inputs into the plantations particularly the fertilisers. I would just like to show you how it is going to affect the position in the plantation industry. The annual consumption is about 130,000 tonnes of fertilisers alone and the additional cost of manuring this time would be about Rs. 6 ijnillion which will on an average increase the cost of production of tea roughly by about 4 paise per kilogram. Since March 1st the Ministry of Food and Agriculture has imposed a countervailing import duty on fertilisers in view of the proposed 10 per cent ad valorem duty and the increase in the price of fertilisers. I will show how it has gone up over the last four years. Sulphate of Ammonia which Was Rs. 374/- a tonne in 1965-66 ^ent up to Rs. 502 in 1968-69 and now with this duty it is going to be Rs. 539. Urea which is extensively used was Rs. 650 per tonne in 1965-66. It went up to Rs. 800 in 1968-69 and with this duty it will now be Rs. 943. I am giving this example of the fertiliser because it is one of the main items in use in the plantations ind any increase in its price will impose a heavy burden on the planta-tjion industry in facing the competi-t|ive markets of the world.

Sir, so many benefits and facilities are provided for the industries. We nd there is a tax holiday for five ears and depreciation allowance on tie entire Sproducing unit which is denied in the case of plantations. There is no such thing as a tax holiday even for new plantations and qepreciation applies only in the case of buildings and machinery only in the plantations and therefore the tax bn gross profits in the plantations is much higher than in the case of industries. And unfortunately plantations are both covered by the Centre is well as the States for taxation purposes and I can tell you that in the three southern States the agricultural income-tax is as high as 60 per cent over a lakh and it does not allow for depreciation on the field assets at all. ibepreciation is allowed only on the buildings and machinery which form only a small part of the capital investments in the plantations. This levy cif wealth tax will hit the plantations particularly hard. I am afraid even s!mall owners of plantations of 25 acres will be covered by this wealth

tax because the valuation of the estates will be on the basis of the market value and if some plantations have changed hands because of investment by industrialists around those areas at a high cost then that will be the market value. As I said even small acreages will be covered bv this wealth tax in addition to the heavier income-tax that we are paying. Here also I am surprised to find that exemptions are not provided for workers' quarters. hospitals, cre-cHes . . .

SHRI R.T. PARTHASARATHY (Tamil Nadu): May I interrupt you for a minute? Do you mean to say that workers' quarters in the estate do not belong to the owner of the plantation? Even though it is occupied by the workers ultimately the value of the property goes in with the estate of which you are the owner.

SHRI U. K. LAKSHMANA COW DA: You must know the position very well being one of the Members of the Coffee Board. I ana not asking for exemption lot a palatial building which might be built by me but I am only asking for exemption for the buildings for the workers. It is a statutory responsibility imposed upon me to provide quarters for the workers and those quarters are to be providsd r. iit-free. If I do not provide this . Purkayastha there will come up and say t have not completed the workers' quarters programme in time and he will take it up under the plantation laws.

SHRI R.T. PARTHASARATHY: Is the worker the owner or are you the owner? It is clear you are the owner. The Government of India is concerned only with the ownership. If you are the owner, then definitely you have got to pay the wealth tax on that.

SHRI U. K. LAKSHMAN GOWDA: I do not know the legal and technical aspect of it. What I am saving is, the plantation owners unlike the owners of industry are obliged by law to provide workers' quarters in the plantations. It is a statutory responsibility on the owners under the

Plantation Act. On the one hand you force me to build these workers' quarters—which of course I will be very happy to build because I want to keep my workers happy and comfortable—but at the same time you want to take that into account for imposing ibis wealth tax and I say that it is not the correct thing to do.

SHRI M. PURKAYASTHA (Assam): Because you pay starvation wages to your workers that is why this plantation law has been enacted.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Otherwise you will not build houses for the workers.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : Anv profit made out of the estate comes under the agricultural income-tax the rates of which I have alreadv said arc very high. In order to provide facilities for the workers I am compelled to build quarters, hospitals, creches, drinking water installations etc. and if you bring all these under the wealth tax it will increase the cost and it will be a great hardship. I say there should be specific exemption pro-vided, so that there will be faster implementation of the plantation Act. And that will be in your interest, Mr. Chitta Basu.

SHRI G. A. APPAN : These people cannot understand our philosophy. Their taxation policy is always irrational. They have double taxation, treble taxation.

SHRI U. K. LAKSHMANA COWDA: What I am saying is, you must provide exemption for these precisely; otherwise you are not doing justice to the plantation in-4 j.m. dustry. These gentlemen seem to think that by nationalising they are going to increase production or better the position of the plantation industry of the country. I am sorry I cannot agree with it. If you will look into the record of the public sector industries, you will find that out of a total investment of Rs. 3,500 crores, tne

[Shri U. K. Lakshmana Gowda.] net loss has been Rs. 3"> crores. If any private industry had run them, I think it would have been out of business.

SHRI G. A. APPAN: You arc underestimating the net loss.

SHRI U. K. LAKSHMANA GOWDA : If the plantation industry is nationalised, I am sure you will not only be ruining the plantation industry. You will he putting lakhs and lakhs of people, who are workers, out of job. I say this because being a labour intensive type of organisation, it is very difficult to run it. You will have to provide sufficient encouragement for the growth of the plantation industry. Otherwise, we will not be in a position to compete in the world market. The production cannot be completely utilised in our own country. We know that fifty per cent of our production has to be exported. If we are to export and earn foreign exchange, it is our primary responsibility to see that the cost of production is kepi low. I am saying that these items which are coming in year after year are not going to keep the cost of production low. On the ultimate question of nationalisation, I do not want to speak. Enough has been said in the Finance Ministry's Report on public sector.

\gain, regarding Central assistance 1 would like to say that plantations are situated in States in very remote areas and there is a great necessity for improving communications. It will eventually help agriculture as we 1. Plantations being situated in the interior jungle areas surrounded by agricultural land, any improvement in road communications will help the growth of the rural areas. It is not possible to take away and put something else in areas where you grow plantation products. II plantation products were not there, I am sure the economy of the rural areas would have suffered very badlv. Yo i cannot have food crops in the hily slopes. The economy of many States, particularly Assam, Kerala, Mysore. Madras and West Bengal, depends to a great extent on plantation products. I would like to say that the Government should give more attention to the development of the plantation industry,

Finally, I come to mv own State of Mysore. Somehow, just like the plantation industry, Mysore seems to have been given a second place in regard to Central assistance. It has been always found, every year, that the Central assistance provided has been the lowest for the State of Mysore, If we take the figure from 19:51 to I9(i», the total investment of 'lie Gentle has been Rs. 2450 crores.

in of that, I will read out a few investments in other States: —

	Rupees in crores
Bihar	356
Madhya Pradesh	459
Madras	245
Orissa	118
West Bengal	108
Mysore	48

SHRI CHITTA liASl): This is in spite of Mr. Nijalingappa being the Chief Minister.

SHRI I k. LAKS IMAXA GOWDA: Yes. Mr. Nijalingappa was

then the Chief Minister and now the President of the Indian National Congress, and in spite of that this is the treatment meted out to Mysore. I would sav that this is very inadequate and the Centre should come out with greater investments and assistance to the State of Mysore. Mysore is a place, as you all know, where there is plenty of electricity and raw materials available for industrial development and it is necessary that the Centre takes advantage of it. We find that dozens of applications for starting new industries recommended from the Government of Mysore have been delayed and the Myosre Chief Minister, who is a Congress Chief Minister, has been complaining every now and then. We know that main irrigation projects, like the Kalindi project, are also delaved in spile or the fact that so many resources and facilities are available in Mysore. The second stage of the Indian Telephone Industries w :ts transferred elsewhere. I am afraid that there is some proposal for shifting the second stage of the Bharat Electronics to some other place. We arc talking so much about regional imbalances, bm where facilities are available and where we can expand the existing units to produce items competitively and at a lower price, that is not done. For political reasons, the second and third stages are shifted to different places. That is not in the interests of the development of the economy of this country. I would strongly stress here that more efforts should be made to provide and nore industries in the Stale of Mysore and also provide greater assistance to the State of Mysore. I hank you.

شری سید حسین (جموں اینڈ کشمیر) : مسٹر وائس چیرمین - میرے لئے مشکل ہے کہ میں مصارف کے لئے اپروپریشن بل پر بحث کروں جب کہ پلاننگ کے بارے میں اس وقت کوئی بحث نہیں - میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی موجودہ ذرائع ہماری سرکار کو ممکن تھے ان سے کام لے کر جو کچھ بھی بجٹ تیار ہوا ہے وہ ایک حد تک ضروریات کو پورا کر سکتا ہے - عام لوگوں کے بارے میں جو فیکٹس اینڈ فیگر پر کیپیٹا انکم کے پرائم منسٹر نے یہاں فرمائے وہ میں اسٹیٹ وائز ریفر کروں گا -

(صوبے)		(روپیوں میں)
آندھرا پردیش	. .	438
آسام	. . .	441
بہار	. . .	299
گجرات	. .	523
هریانه	. .	504
جموں و کشمیر	. .	341
کیرالا	. .	393
مدھیہ پردیش	. .	373
مہاراشٹر	. . .	526
میسور	. . .	42C

[Syed Ahmed]

State	Rs.
ناگا لینڈ	[illegible]
اڑیسہ	347
پنجاب	575
راجستھان	356
تامل ناڈ	434
اتر پردیش	374
ویسٹ بنگال	498

اس سے ظاہر ہے کہ ہمارے لوگوں کی سالانہ پر کیپیٹا انکم کیا ہے - میں یہاں ایک ورس کوٹ کرتا ہوں -

آ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر اُمم کیا ہے
شمشیر و سناں اول طاؤس و رباب آخر -

I will explain to you what the destiny of a nation is. First they labour and struggle. Then they enjoy themselves.

اور جس وقت وہ عیش و آرام میں لگتے ہیں That is the end of the nation. میں ادب سے گذارش کرونگا کہ عام جنتا جنہوں نے انگریز سے ہندوستان لیا وہ سمجھتی نہیں ہے کہ ابھی اس کا ہندوستان بنا ہے - میں سمجھتا ہوں وہ قدروں سے گمراہ نہیں ہے کونسی ویلیوز ہم سامنے رکھیں - ہماری قوم نہ ہی رشیا کا غلام بننا پسند کرتی ہے نہ ہی امریکہ کا - میں یہاں ضرور یہ کہوں گا کہ ہمارے غریب لوگوں کی تین بیسک ضرورتیں ابھی پوری نہیں ہوئیں ہیں

پچاس کروڑ لوگوں کی اکثریت کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے - یعنی خوراک اور شیلٹر - ۵۳ کروڑ کے قریب لوگ - فرماتے ہیں - ہوگئے - ان کی بیسک نیڈس واٹر - فوڈ اینڈ شیلٹر بیسک تین ضرورتیں جن کو فائننس منسٹر صاحب نے بھی کوٹ کیا ہے ابھی پوری نہیں ہوئی ہیں - تو آپ پر کیپیٹا انکم سے سمجھ گئے ہیں کہ کہ ہماری عام جنتا غریب ہے اور اقتصادی کنٹرول کن ہاتھوں میں ہے کب تک ہم لوگوں کی خواہشات سے آنکھیں بند کرتے رہینگے - خیر میں یہ گذارش کروں گا کہ گاندھی جی نے جو راستہ ہمیں بتایا - پنڈت جی نے جو راستہ ہمیں دکھایا لوگوں کو اس راستہ پر زیادہ یقین ہے - ڈیموکریسی پر یقین ہے اور لوگ متحد ہوتے ہیں جب حملہ ہوتا ہے بھلے ہی وہ حملہ چین کرے یا پاکستان کرے - وہ خطرہ اتنا نہیں ہے کیونکہ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں - لوگ مقابلہ کرتے ہیں اور

چھاتیاں ابھار کر گولیاں کھاتے ہیں - جمہوریت پر یہاں کے لوگوں کا یقین ہے اور یہ چیز ایک کامیابی ہے - پنڈت جواہر لال کے ان آدرشوں کی، گاندھی جی کے ان آدرشوں کی - لوگوں کو اس بات پر یقین ہوا ہے کہ ہم ڈیمو کریٹک وے آف لائف اڈاپٹ کر چکے ہیں - جس کے سامنے ہمارے دشمنوں نے شکست کھائی ہے - ہمارے بھائی دوسری طرف کے جو کہ پورے ۲۱ سال سے زبان نہیں کھول سکے ہیں وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں جمہوری آدرش کامیاب بنانے میں - سیکولرزم قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہے کہ اس بنیاد پر ہم کھڑے ہوئے ہیں اس بنیاد پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس بنیاد پر ہم نے انگریزوں کو بھگایا لیکن ان پر شدت سے کام کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے -

[illegible]

[illegible]

میں ایک مثال بتاؤں گا - میں خوش قسمتی سے اس اسٹیٹ سے ہوں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کشمیر پر بہت خرچ ہوا - میں کہتا ہوں کہ کشمیر کے نام پر خرچ ہوا ہے -

Much has been spent on Kashmir, that is, in the name of Kashmir, but very little has been spent in Kashmir.

کہا یہ سچ نہیں ہے - دہ اور حال میں آواز آئی کہ ۲ کروڑ کا وہاں نقصان ہوا ہے برف گری اور پھر اخبار میں آیا کہ ۹ کروڑ کا نقصان ہوا اور میرے پاس ایک اخبار ہے جو کانگریس گورنمنٹ کو سپورٹ کرنے والا اخبار ہے اور اس نے سچ بات لکھی ہے کہ وہاں بے وقت برف پڑی جس کی وجہ سے ۲۰ کروڑ کا لاس ہوا ہے - کشمیر کے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کہا کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے - میں سمجھتا ہوں کہ انکو کسی طرح سے بھی زیادہ سے زیادہ مدد ملنی چاہئے وہاں گلمرگ میں ایٹامک آبزرویٹری ہے، وہاں آبزرویشن ہو رہا ہے - چین جو ایکسپلوژن کرتا ہے اس کی وجہ سے ایسے ذرات ہوا میں ملے ہیں جس کی وجہ سے ہی ایسی آوٹ آف سیزن برف پڑی ہے اپریل کے لاسٹ میں کہ جتنا ہمارا فروٹ تھا، کراپ تھی، چیری، اخروٹ، سیب وہ سب تباہ ہو گیا اور وہ کشمیری غریب جن کی پر کیپیٹا انکم میں نے دیکھی کہ سب سے کم ہے -

[Syed Ahmed]

Minus one State; I can quote that, Bihar.

ہمارے بہار کے بھائی ہم سے کچھ پوچھے ہیں تو میں ادب سے گذارش کروں گا کہ اکیس سال سے کہا جاتا ہے کہ کشمیر نے ترقی کی ہے - میں خوشی سے کہتا ہوں کہ پہاڑوں کے بیچ میں جہاں کہ راستے نہیں تھے راستے بنائے گئے - کارخانہ وہاں کوئی نہیں ہے، انڈسٹری کے بارے میں میں نے پوچھا انڈسٹری منسٹر صاحب سے اور میں اسے پڑھ کو سناؤں - لکھا ہے -

"The provisions for outlays on industries and mining during the Third Plan and in the last three Annual Plans have not been fully utilised by the State Government."

This is the reply from the Central Government.

ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ علیحدہ ہیں - ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ عام جنتا جو ہے وہ بہت غریب ہے - ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں-

There is a yawning gap between them and the common and downtrodden people everywhere.

میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو پالیسی ہے اس کے مطابق آج جو پیسہ ہم خرچ کرتے ہیں - جن ہاتھوں سے خرچ کرتے ہیں وہ اس مقصد کو پورا نہیں ہونے دیتا - اور اس کی وجہ سے اکثر گورنمنٹ فیل ہوتی ہیں چاہے وہ اپوزیشن کی ہوں یا کانگریس کی - خوش قسمتی سے میں کانگریس کا

کہ جموں کشمیر میں کانگریس دونوں طرف سے کامیاب ہوئی ہے - جموں و کشمیر کے لوگوں نے اور لداخ کے لوگوں نے کانگریس کا ساتھ دیا ہے - ریسینٹ الیکشن میں قریب قریب ساری سیٹیں کانگریس نے جیتی ہیں صرف اس لئے کہ کانگریس سیکولر ہے اور وہاں کے لوگوں کا فیصلہ صحیح ہے - مگر میں یہ عرض کروں گا کہ جن ہاتھوں کے ذریعہ ہم کام کرانا چاہتے ہیں وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ہم لوگوں سے دور جا رہے ہیں - میرا سجیشن ہے کہ ہم ایک کمیٹی بنائیں جو عام جنتا کی ضرورتوں — پانی ، مکان اور رہنے کی جگہ کی رورل ایمپلائمنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اس بارے میں غور کرے یہ میری گذارش ہے - میں کشمیر کی انڈسٹری کے بارے میں گذارش کرنا چاہتا ہوں - ہمارے یہاں سے فروٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا اور پچھلے سال ہمارے چیف منسٹر نے کہا تھا کہ وہ قریب سات کروڑ کے ایکسپورٹ ہوا تھا - افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے

که اب جب که همارا لاس ۱۹ کروڑ کا هے - دولت کی کراپ هماری برباد هو گئی - وائس چیرمین صاحب — اب وه گیا ان سپورٹ کو پانچھیں گے اور هم وهاں امپورٹ کیا کر رهے هیں - یه میں جاننا چاهتا هوں آپ نے جواب دیا هے که سیمنٹ فیکٹری وهاں هے - وه اس وقت کی هے جب که شیخ عبدالله صاحب حکومت چلاتے تھے - میں خوشی سے کهوں گا که بخشی غلام محمد کے سمے کچھ هوا هے - میں اسے بهت اپریسیشن دیتا هوں - کانگریس میں رہ کر کیونکه میں امپارشل طریقه سے بات کرتا هوں - جهاں تک گورنمنٹ کا تعلق هے میں سمجھتا هوں که اس نے کچھ کیا هے لیکن آپ دیکھیں که اس کا ایڈوانٹیج کون لیتا هے - کوئی نهیں لیتا - ایڈوانٹیج اگر کوئی سمجھے که ملتا هے تو وه اسے نهیں ملتا - ایڈوانٹیج دوسرے کو ملتا هے جو وهاں کے دلال لوگ هیں ان کو ایکسپلائٹ کیا جا سکتا هے حالانکه آج تک هم نے یه شکست دی هے کیونکه اس کے مقاصد یہاں زیادہ اور جمهوری زندگی هے

There is a purpose of unity before us and we have achieved that purpose of unity. Democratic way of life we have achieved.

تو میں عرض کروں گا که همارے کشمیر میں کوئی بڑا کارخانه نهیں هے میڈیکل کالج اور اسٹیٹس میں زیاده هیں - اور همیں شکایت اس بات کی هے که جاپان سے ایگریکلچر کے ۹ یا ۱۰ یونٹ آئے لیکن هم کو ایک بهی نهیں ملا - تو میں یه عرض کروں گا که همارے یہاں انجینیرینگ کالج هو، میڈیکل کالج هو، جو همیں وه همارا پروز پورا نهیں کرتے - میں گورنمنٹ سے پوچھنا چاهتا هوں که انگھوروں بو پھلنے کے کوگل هم اپنے ملک میں بناتے هیں اس بات کا همیں فخر هے - بلیڈ هم بناتے هیں - گھڑی هم بناتے هیں لیکن آج کے بڑے آدمی جو ریڈیو گرام رکھتے هیں - ٹرانزیسٹر رکھتے هیں اس بات کی کوشش کرتے هیں که وه فارن هوں - هم اس بات کی کوشش کرتے هیں که باهر جائیں تو بچوں کے لئے فارن چیزیں لائیں - میں پوچھنا چاهتا هوں که هندوستان کی بنی هوئی چیزوں میں سے کون سی هم کشمیر میں بناتے هیں ؟ کیا هم بلیڈ بناتے هیں ؟ کیا هم وهاں فاؤنٹین پین بناتے هیں ؟ کیا هم وهاں ٹیلیفون یا گھڑیاں بناتے هیں ؟ هم ایک بلیڈ اور پنسل بهی نهیں

[Shri Syed Hnss'an]

بنا سکتے - ہم ایک چھوٹی بھی نہیں
بنا سکتے - اس کا مطلب یہ ہے کہ
کشمیر صرف ایک تماشہ کی جگہ
ہے - وہ نیچرل ہے ، وہاں ہوا ہے ، پانی
ہے ، ٹھنڈک رہتی ہے لیکن وہاں کے
غریبوں کے لئے وہ جنت میں جہنم ہے
اور یہ ہم کس سے کہیں - ہم ۵۰ کروڑ
لوگوں سے نظریں ملائے ہوئے ہیں - ہم
دوسروں کی طرف نہیں جاتے - ہم
امریکہ کی ہمدردی میں نظر ملائے
نہیں بیٹھے ہیں - ہم نے ۵۰ کروڑ
ہندوستانیوں کے ساتھ نظریں ملائیں
اور دل ملایا اور ان سے ہم کو جو آشا
تھی انہوں نے اس کو پورا کر دیا -
یہاں کے جوانوں نے ثابت کر دیا جب
حملہ ہم پر ہوا تو سینا آئی اور
اس نے ہم کو آپ کو بچایا ، ہندوستان
کو بچایا اور اگر یہ مدد کرتی ہے تو
ہندوستان کے ۵۰ کروڑ لوگوں کی مدد
کرتی ہے ، اس میں احسان کس کا
ہے ؟ میں نہایت ادب سے گذارش
کروں گا کہ ہمیں کیا چاہئے - پلاننگ
کے متعلق نہیں کہوں گا کیونکہ وہ زیر
بحث نہیں ہے لیکن اس ہاؤس میں
عرض کروں گا کہ لوگ بہت غریب
ہوئے ہیں رورل ان امپلائمنٹ ہے ،
کوئی انڈسٹری وہاں نہیں ہے اور اس
رقبہ ۲۰ کروڑ کا وہاں نقصان ہو گیا
تو وہ لوگ ہندوستان کے عوام کی
طرف دیکھ رہے ہیں اور یہ ہماری
بدقسمتی ہوگی اگر ہماری سرکار پوری
طرح سے اس طرف دھیان نہیں
دیگی -

†[**श्री सैयद हुसैन** (जम्मू और काश्मीर) : मिस्टर वाइस चेयरमैन, मेरे लिए मुश्किल है कि मैं मसारिफ के लिए एप्रोप्रीएशन बिल पर बहस करूं जबकि प्लानिंग के बारे में इस वक्त कोई बहस नहीं। मैं समझता हूं कि जो भी मौजूदा जराए हमारी सरकार को मुम्किन थे उनसे काम ले कर जो कुछ भी बजट तैयार हुआ है वह एक हद तक जरूरियात को पूरा कर सकता है। आम लोगों के बारे में जो फेक्ट एण्ड फिगर पर कैपिटा इंकम के प्राइम मिनिस्टर ने यहां फरमाए वे मैं स्टेट वाइज रेफर करूंगा :—

(सूबे)	(रुपयों में)
आन्ध्र प्रदेश . .	438
आसाम . .	441
बिहार . .	299
गुजरात . .	523
हरियाणा . .	504
जम्मू व काश्मीर .	341
केरल . .	393
मध्य प्रदेश . .	373
महाराष्ट्र . .	526
मैसूर . .	420
नागालैंड . .	—
उड़ीसा . .	347
पंजाब . .	575
राजस्थान .	356
तमिल नाडु . .	434
उत्तर प्रदेश . .	374
वैस्ट बंगाल . .	498

† Hindi Translation.

इससे जाहिर है कि हमारे लोगों की सालाना पर केपिटा इंकम क्या है। मैं यहां एक वरस कोट करता हूं—

आ तुझ को बताऊं मैं तकदी-रे-उमम क्या है, शमशीरो सिनान अव्वल ताऊस-व रूबाब आखिर।

I will explain to you. What is the destiny of a Nation, is. First they labour and struggle then they enjoy themselves that is the end of the Nation.

और जिस वक्त वह ऐश व आराम में लगते हैं, मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि आम जनता जिन्होंने अंग्रेज से हिन्दुस्तान लिया वह समझती नहीं है कि अभी इसका हिन्दुस्तान बना है। मैं समझता हूं वह कदरों से गुमराह नहीं है कौन सी वेल्यूज हम सामने रखें। हमारी कौम न ही रशिया का गुलाम बनना पसन्द करती है न ही अमरीका का। मैं यहां जरूर यह कहूंगा कि हमारे गरीब लोगों की तीन बेसिक जरूरतें अभी पूरी नहीं हुई हैं।

पचास करोड़ लोगों की अक्सरीयत की जरूरत पूरी नहीं होती है—पानी खुराक और शेल्टर—53 करोड़ के करीब लोग फरमाते हैं, हो गये। उनकी बेसिक नीड्स वाटर, फूड एण्ड शेल्टर बेसिक तीन जरूरतें जिनको फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी कोट किया है, अभी पूरी नहीं हुई हैं। तो आप पर कैपिटा इंकम से समझ गये होंगे कि हमारी आम जनता गरीब है और इक्तसादी कन्ट्रोल किन हाथों में है कब तक हम लोगों की ख्वाहिश से आंखें बन्द करते रहेंगे। खैर मैं यह गुजारिश करूंगा कि गांधी जी ने जो रास्ता हमें बताया, पंडित जी ने जो रास्ता हमें दिखाया लोगों को इस रास्ते पर ज्यादा यकीन है। डेमोक्रेसी पर यकीन है और लोग मुत्ताहिद होते हैं जब हमला होता है भले ही वह हमला चीन करें या पाकिस्तान करें। वह खतरा इतना नहीं है क्योंकि लोग इस वक्त हमारे साथ होते हैं। लोग मुकाबला करते हैं और छातियां उभार कर गोलियां खाते हैं। जम्हूरियत पर यहां के लोगों का यकीन है और यह चीज एक कामयाबी है। पंडित जवाहर लाल के उन आदर्शों की गांधी जी के उन आदर्शों की लोगों को इस बात पर यकीन हुआ है कि हम डेमोक्रेटिक वे आफ लाइफ़ अडाप्ट कर चुके हैं। जिस के सामने हमारे दुश्मनों ने शिकस्त खाई है। आज हमारे भाई दूसरी तरफ के जो कि पूरे 21 साल से जबान नहीं खोल सके हैं वे इस बात का एतराफ करते है कि हम कामयाब हुए हैं। जम्हूरी आदर्श कामयाब बनाने में सैक्युलरइज़म कायम करने में हम कामयाब हुए हैं यह ठीक है कि इस बुनियाद पर हम खड़े हुए हैं। इस बुनियाद पर हम इकट्ठे हुए है, इस बुनियाद पर हमने अंग्रेजों को भगाया लेकिन उन पर शिद्दत से काम करने की हमें जरूरत है।

मैं एक मिसाल बताऊंगा मैं खुशकिस्मती से उस स्टेट से हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि काश्मीर पर बहुत खर्च हुआ। मैं कहता हूं कि काश्मीर के नाम पर खर्च हुआ है।

Much has been spent on Kashmir, that is in the name of Kashmir, but very little has been spent in Kashmir.

क्या यह सच नहीं है कि अभी हाल में आवाज आई कि 2 करोड़ का वहां

[श्री सैयद हुसैन]

नुकसान हुआ है। बर्फ गिरी और फिर अखबार में आया कि 9 करोड़ का नुकसान हुआ और मेरे पास एक अखबार है जो कांग्रेस गवर्नमैंट को स्पोर्ट करने वाला अखबार है और इसने सच बात लिखी है कि वहां बे वक्त बर्फ पड़ी जिस की वजह से 20 करोड़ का लास हुआ है। काश्मीर के चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या करते है उन लोगों के लिए। मैं समझता हूं कि उन को किसी तरह से भी ज्यादा से ज्यादा मदद मिलनी चाहिए वहां गुलमर्ग में एटामिक आबजर्वेट्री है वहां आबजर्वेशन हो रहा है। चीन जो एक्सप्लोजल करता है उसकी वजह से ऐसे जरात हवा में मिले हैं जिसकी वजह से ही ऐसी आऊट आफ सीजन बर्फ पड़ी है। अप्रैल के लास्ट में कि जितना हमारा फूड था, क्राप थी चेरी, अखरोट, सेव वे सब तबाह हो गया और वह काश्मीरी गरीब जिन की पर केपिटा इंकम मैंने देखी कि सबसे कम है

Minus one state; I can quote that Bihar.

हमारे बिहार के भाई हम से कुछ पीछे हैं तो मैं अदब से गुजारिश करूंगा कि 21 साल से कहा जाता है कि काश्मीर ने तरक्की की है। मैं खुशी से कहता हूं कि पहाड़ों के बीच में जहां कि रास्ते नहीं थे रास्ते बनाए गये। कारखाना वहां कोई नहीं है, इण्डस्ट्री के बारे में मैंने पूछा इण्डस्ट्री मिनिस्टर साहब से और मैं उसे पढ़ कर सुनाऊं—लिखा है—

"The provisions for outlays on industries and mining during the Third Plan and the last three Annual Plans have not been fully utilized by the State Government". This is the reply from the Central Government.

हमारा मसला यह नहीं है कि हम कुछ इलादा हैं। हमारा मसला यह है कि आम जनत जो है, उनके पास सिसोसिज नहीं हैं—

There is yawning between them and the common and down-troden people every where.

मैं यह कहूंगा कि हमारी जो पालिसी है उसके मुताबिक आज जो पैसा हम खर्च करते हैं जिन हाथों से खर्च करते हैं वह इस मकसद को पूरा नहीं होने देता। और इसकी वजह से अक्सर गवर्नमेंट फेल होती हैं चाहे वह अपोजीशन की हों या कांग्रेस की। खुश किस्मती से मैं कांग्रेस का मेम्बर हूं मुझे फिख्र है इस बात का कि जम्मू काश्मीर में कांग्रेस दोनों तरफ से कामयाब हुई है। जम्मू व काश्मीर के लोगों ने और लद्दाख के लोगों ने कांग्रेस का साथ दिया है। रिसेंट इलेक्शन में करीब करीब सारी सीटें कांग्रेस ने जीतीं हैं सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस सेक्यूलर है और वहां के लोगों का फेसला सहीं है। मगर मैं यह अर्ज करूंगा कि जिन हाथों के जरिए हम काम कराना चाहते हैं वह इस मकसद को पूरा नहीं करते जिस का नतीजा यह होता है कि लोग हम से दूर हो जाते हैं और हम लोगों से दूर जा रहे हैं। मेरा सजेशन है कि हम एक कमेटी बनाएं जो आम जनता की जरूरतों—पानी मकान और रहने की जगह की, रूरल इम्पलाइमेंट की रेमीडी क्या है, इस बारे में गौर करे यह मेरी गजारिश है। मैं काश्मीर की इण्डिस्ट्री के बारे में गुजारिश करना चहता हूं। हमारे यहां से फ्रूट एक्सपोर्ट होता था और पिछले साल हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि वह करीब सात करोड़ के एक्सपोर्ट हुआ था। अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अब जब कि हमारा लास 19 करोड़ का है, फ्रूट की क्राप हमारी बरबाद हो गई। वाइस चेयरमेन साहब, अब वह क्या

एक्सपोर्ट कर पाएंगे और हम वहां इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं। यह मैं जानना चाहता हूं। आप ने जवाब दिया है कि सीमेंट फैक्टरी वहां है। वह उस वक्त की है जब कि शेख अब्दुला साहब हकूमत चलाते थे। मैं खुशी से कहूंगा कि बख्शी गुलाम मुहम्मद के समय कुछ हुआ है। मैं इसे बहुत अप्रीसेशन देता हूं। कांग्रेस में रह कर क्योंकि मैं इम्पार्शल तरीके से बात करता हूं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि इसने कुछ किया है, लेकिन आप देखें कि इस का एडवंटेज कौन लेता है। कोई नहीं लेता। एडवंटेज अगर कोई समझे कि मुझे मिला तो वह इसे नहीं मिलता। एडवंटेज दूसरे का मिलता है जो वहां के बद-हाल लोग हैं उनको एक्सपलायट किया जा सकता है हालांकि आज तक हमने उसे शिकस्त दी है क्योंकि इसके खिलाफ एक आइडियालोजिकल यूनिटी है—

There is a purpose of unity before us and we have achieved that purpose of unity. Democratic way of life we have achieved.

तो मैं अर्ज करूंगा कि हमारे काश्मीर में कोई सरकारी कारखाना नहीं है। मेडिकल कालेज और स्टेटस में ज्यादा हैं और हमें शिकायत इस बात की है कि जापान से एग्रीकल्चर के 9 या 10 यूनिट आए लेकिन हमको एक भी नहीं मिला। तो मैं यह अर्ज करूंगा कि हमारे यहां इंजीनियरिंग कालेज हो मेडिकल कालेज हो, जो हैं वे हमारा परपज़ पूरा नहीं करते। मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आंखों पर पहनने के गोगल हम अपने मुल्क में बनाते हैं इस बात का हमें फिख्र है, ब्लेड हम बनाते हैं, घड़ी हम बनाते हैं लेकिन आज के बड़े आदमी जो रेडियोग्राम रखते हैं, ट्रांजिस्टर रखते हैं इस बात की कोशिश करते है कि वे फारेन हों। हम इस बात की कोशिश करते हैं कि बाहर जाएं तो बच्चों के लिए फारेन चीजें लाए। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की बनी हुई चीजों में से कौन सी हम काश्मीर में बनाते हैं ? क्या हम ब्लैड बनाते हैं ? क्या हम वहां फाउंटेंन पेन बनाते हैं ? क्या हम वहां टेलीफोन या घड़ियाँ बनाते हैं ? हम एक ब्लैड और पेंसिल भी नहीं बना सकते। हम एक चमचा भी नहीं बना सकते। इसका मतलब यह है कि काश्मीर सिर्फ एक तमाशा की जगह है। वह नेचुरल है, वहां हवा है, पानी है ,ठंड रहती है लेकिन वहां के गरीबों के लिए वह जन्नत में जहन्नुम है और यह हम किस से कहें। हम 50 करोड़ लोगों से नज़रें मिलाए हुए हैं। हम दूसरों की तरफ नहीं जाते। हम अमरीका की हमदर्दी में नज़र मिलाए नहीं बैठे हैं। हमने 50 करोड़ हिन्दुस्तानियों के साथ नज़रें मिलाई और दिल मिलाया और उनसे हम को आशा थी उन्होंने उसको पूरा कर दिया। यहां के जवानों ने साबित कर दिया जब हमला हम पर हुआ तो सेना आई और उसने हम को, आप को बचाया हिन्दुस्तान को बचाया और अगर यह मदद करती है तो हिन्दुस्तान के 50 करोड़ लोगों की मदद करती है इसमें अहसान किस का है। मैं निहायत अदब से गुजारिश करूंगा कि हमें क्या चाहिए। प्लानिंग के मुत्तलक नहीं कहूंगा क्योंकि वह ज़ेर-बहस नहीं है लेकिन इस हाउस में अर्ज करूंगा कि लोग बहुत गरीब हुए हैं, रूरल अन-इम्प्लाइमेंट है, कोई इण्डिस्टरी वहां नहीं है और इस वक्त 20 करोड़ का वहां नुकसान हो गया तो वे लोग हिन्दुस्तान के अवाम की तरफ देख रहे हैं और यह हमारी बद-किस्मती होगी अगर हमारी सरकार

[श्री सैयद हुसैन]

पूरी तरह से इस तरफ ध्यान नहीं देती ।]

SHRI G. A. APPAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, at the outset, I am not very happy at the Government's attempt to come here with a large number of items asking for the ratification or the permission of this august House to sanction the amounts provided there in this Appropriation Bill. I can say with all the modesty at my command that all the policies and programmes of the Government of India could be run with half the amount that is being now spent every year. The amounts that are provided for under these heads are extraordinarily unwarranted, unrealistic and irrational in approach, for most of the money that is being asked for is being spent on big officers and on prestige policies and programmes rather than on Plan priorities of an indispensable nature. Any good economist, any good administrator, could run the Government; any good Finance Minister could budget them all with only half the amount that is being now asked for from Parliament for the continuance of all the activities now adumbrated. The Government of India's Budget is rather too large and too uncompromising for such a poor country as ours. The division of India into linguistic States is a great burden on the poor resources of the country. Adult suffrage is given indiscriminately. Though most people might judge that it is good, I do not agree here, for with this extent of illiteracy in this country, where is the need for this costly adornment and gamble of adult suffrage? I know for certain—I have my electoral experiences—that people are selling their votes even for one puliodarai potlam or for four annas etc. People come outside the booths with their votes and sell them. For people who can sell costly votes, valuable votes, even for one puliodarai potlam or for four annas, etc. where is the need for adult suffrage? This is unwarranted unless all the people are educated sufficiently about the value of adult suffrage, that even a single vote can topple a whole Government. There is no need for this adult suffrage. Before adult suffrage is publicly and properly utilised, the Government should come out and make it their first and foremost policy to educate the electorate on the value of this suffrage. Furthermore, where is the need for this adult suffrage in a country of illiteracy? First of all, the Constitution provides that within ten years from the commencement of the Constitution education up to 14 years should be made compulsory and free for all. What is the percentage of literacy now? Is it more than 25 or 30 per cent? When you could not maintain what you promised or at least what you proposed to do, there is no need for such a tall talk and false day-dreams to do propaganda about what you cannot achieve or accomplish.

The industrial policy of the Government is another grave mistake that they have themselves committed to. Rather than developing the small scale industries, the agro-industries, the cottage industries and things like that, we have now adumbrated or we have greater reliance on or scope for, building up costly industries and nationalised industries. Where is the need for the nationalisation of industries when you cannot aim at or bring about profitability? Is it industry? Why should you run such costly games? After all, they cannot be based on prestige policies. And when there are entrepreneurs who can run these industries, the Government need not put spokes in the running wheel of Indian economy.

The Educational Budget that is coming up is another great blunder. Of course, education has to be given freely and compulsorily up to a certain stage, and not up to all standards, up to post-graduate and doctorate standards. To whom does it go? It goes to the vested interests and the wealthy people. And research also is not being done on scientific lines. As long as we can utilise the benefits of other countries or follow people who have great experience in

research, why should we waste our money and time in these prestige policies for namesake?

There are three things which are very important—food, shelter and clothing. Regarding food, we have a vast area, a vast expanse of land lying idle. Should not the Government try to take canals to all the waste and arable lands and put them into cultivation, under tractor or mechanised cultivation, rather than taxing the poor people, the commercial people, the business people, the industrialists, up to the throat? And ihev have to pay through their nose. This is being done. The canons of taxalion are that the people should not feel that they are paying; they should not hesitate to pay if it is a normal, bearable level of taxation. When the taxation is heavy they try to evade. When you are not collecting the full revenue of tax what is the use of your taxation at all? This morning, the Finance Minister said that there are thousands of people who evade taxes to a limit of one lakh and ten lakhs. What are your officers doing? What is the use of your taxation? If an officer is not able to do his duty satisfactorily. . . .

SHRI P. C. SETHI: May I correct him? They were figures of arrears, not of evasion.

SHRI G. A. APPAN: Anyhow, coming to the point of agriculture, Government will have to spend at least a large portion of their money, their surplus reserve, on the development of agriculture, on the welfare of these farmers and agriculturists. On account of the fragmentation of holdings into small holdings—we do not have larger holding—the economv of agricultural labour is very very deplorable. The agriculturists of India are born in debt, they live in debt and they die in debt. What do the Government do to relieve them of iheir pitiable plight? They will have to be given all financial assistance, long-term loans, medium-term loans and short-term loans at a reasonable rate of interest, not at an interest of 12 or 13 per cent.

As a farmer I know that in the villages the farmers get loans at the usurious interest of even a hundred per cent. Should not the Government come forward to relieve this very painful anguish of borrowing at usurious rates of interest rather than spending all our money on these drought schemes, flood prevention si hemes etc. Why not have a big canal from the Ganges to connect the Southern parts of India? If the big rivers of the North are connected with the smaller rivers of the South there will be perennial flow of water; there will be no scarcity of water. The water that is now going into the sea as a waste could be tapped, canalised and usefully utilised rather than allowing it to flow away into the sea.

Apart from that, all the waste lands that are lying fallow should be given free to everybody in the country who have no land and not for people who will simply keep it in their name; it should be given to the actual tillers of the soil. How many people are starving without any land, without any land to live on. I would rather appeal to the Government to take a correct statistics of the arable waste land, hill tracts and river beds etc. and to distribute them to the landless labourers within two or three years from now.

Coming to the point of education, I have once again to say that education, though a State subject, the Government of India have got their own responsibility. Higher education can be given free to everybody as part-time education. In this connection may I draw the attention of this august House to the representation which I sent to the Government of India in 1946 and to the various State Governments that education can be provided free as part-time education to outside candidates for the various University examinations, graduation, post-graduation and doctorate standards?

Regarding the development of cottage industries, the use of techno- rafts lias to be made fully rather than

[Shri G. A. Appan.]

putting in ordinary people, ordinary graduates, vested interests as in-charge. lake, for instance, the Khadi and the Village Industries Department and the activities of the Khadi and Village Industries Commission. May I submit to this august House that immediately a Commission will have to be appointed with at least five people as its members, people connected with the khadi and village industries work, to go into the working, efficiency and economy and the profitability of every sector there. Many of the people in the Khadi and the Village Industries Department are prestige people who have come there by favouritism and things like that. Take, for instance, the Department of Khadi and Village Industries in my State. An ordinary man is getting Rs. 1,200 p.m. because he belongs to the ruling party at the Centre. Another failed intermediate has been getting more than a thousand rupees. An ordinary B. Sc, a great enemy of the Scheduled Castes, Mr. S. Padmanabhan, is the Secretary of the Khadi and Village Industries Commission. He was appointed there to implement the prestige policy of the Congress people then. He has terrorised the whole staff of the Khadi and Village Industries Department. He should be immediately suspended. Similarly, a number of senior officers appointed by the previous Congress Ministry under favouritism, who have been misfit-, should be immediately suspended and a Commission should be appointed to look into the economy of the Department, and the question of appointment of Scheduled Castes. Not a single Scheduled Castes man is there in the whole of the Khadi and Village Industries Department. We should also immediately appoint a committee to look into the question of the administration of the khadi and village industries. We should try to improve the scope of the kisan charkha and its products rather than spending a lot of money over this ambar charkha. programme and the uneconomic policies of the Depart ment that are being pursued for the sake of prestige. [Time Bell rings) Two more minutes.

Regarding the question of printing and stationery. Mr. Vice-Chairman, it is a pity that the finance Department and the Secretariat here do not have any sense of proportion in spending money over stationery. Mr. Vice-Chairman, I am getting, side by side with the English version, the Hindi version of the Budget papers. I do not know anything about Hindi. I do not know win they force down my throat the Hindi version along with the English version. Is it the intention of some of these wonderful Ministers to penalise me b\ this burden of rotten siuli of this Hindi material? Should they not care to save money over printing and the paper which is a scarce commodity in India and divert it to the people who have better use of i(? Whv should thev waste money ....

SHRIMAII I.ALITHA (RAIA-GOPALAN): You can ask them not to waste money. But do not call it "rotten". How do you say it is rotten?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI-D. THENGARI): Mr. Appan, that is not the subject-matter of discussion here.

SHRI G.A. APPAN: Anyway, the money that is now being spent over the printing and paper of the Budget will have to be reduced by half.

1 hen. lake the simultaneous translation that is being done here. What a waste? Is it not a penalty for people like us? It is an august House. These people want a salary of Rs. 1,000 or Rs. 1,200 per month. Could our Members not understand one language? When vou can be satisfied with one commodity whv do you want to waste your money over three or four commodities? When you have delicious Laddoo to take, why do you want peas and murukku.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): You may kindh desist from discussing this problem of simultaneous translation because it is introduced by the Chairman.

SHRI A. APPAN: Anyhow, we will have to appoint a small Committee to look into this whose question of expenditure.

SHRI AKBAR ALI KHAN Would it not mean expenditure?

.SHRI G. A. APPAN: Mr. Ruthna-swamy put. a verv, very wise question when he asked how far are we able to economise on our administration. We should have smaller committees, not with 30 or 40 members; let us have one member from each region knowing accountancy, audit, costing, management, import, export, production, managerial efficiency, administrative efficiency, political administration and all other things to look into all these things. Therefore, T do not know what our committees do, and even when these committees submif their reports I do not know why those reports are not implemented at all. I would rather say that smaller committees should be appointed rather than big ones.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): Please wind up.

SHRI G. A. APPAN: I leave it to ih,' Government, the hon'ble Minister here to please reply every point that I have raised whether it is rational or irrational and how far it is going to he implemented from now itself rather than later.

SHRI SANDA NARAYANAPPA (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman. Sir, the Appropriation (No. .") Bill is under discussion in our House now and I am supporting the Bill. We have passed such Appropriation Bills evety vear since we attained independence. Bui whal is the result of passing these Appropriation Bills? This needs to be carefully considered. Under each Ministry huge amounts have been allocated in the Appropri a don Bill. The question now to be considered is whether the national income has increased or the per capita income of an individual has increased. If these two questions are put. I think the answer will be in the negative. In this connection, the Prime Mini-ster of India has recently said that for SO per cent of the population in the country, the level of income and standard of living is below average, and that necessary attention should be bestowed for their development and for the improvement of the condition of the common man. But, considering the present position of the economy of our country, are our Appropriation Bills going in the right direction in order to improve the condition of the common man in the country?

Now, Sir, I come to the handloom sector which is an important sector in the country. Millions of people are depending upon this handloom industry. Woollen handloom industry is there: silk handloom industry is there; and cotton handloom industry is there. These people are not well educated. Neither are they able to agitate nor are they able to start strikes to draw the attention of the Government. They are very meek and disciplined and they stick to their looms. Bui they arc not able to earn sufficient income from this industry. Manx concessions have recently been given to the cotton textile mill industry. There are nearly 300 to 400 mills in the country and they are economically sound. And the people who have invested capital in this mill industry are capable of starting agitations and bringing pressure on the Government to draw attention to the difficulties they arc confronted with in their industry. And the Government gives some concessions to the textile mill industry as well as to the powerloom industry. Recently, Sir, when this Bill was under consideration before the Lok Sabha. some concessions were given for the products of the power-loom and the mill industries, whereas the handloom industry has been completely neglected and their representa-tions have not been considered. Only up to 40 count of varn is exempted from excise duty. That is the only concession that thev have given. They have set up an All India Handloom Board and through that Board they are giving certain facilities. Hitherto they were giving a rebate on the sale

|Shri Sanda Narayanappa,] of handloom cloth. Now that has been dispensed with. And the facilities that were created through cess fund for the development of this handloom industry and for the promo-lion of export of handloom cloth to other countries have also been neglected. Only they are celebrating ever) year Handloom Weeks and other things. But that docs not give much benefit to the handloom industry. Some propaganda will he carried out. some pamphlets will be distributed, some meetings will be organised and some money will be spent on this propaganda and other schemes. But do these help the handloom industry really? Take, for example, the composite mills. They are getting yarn at a cheaper rate. Soon after cotton is converted into yarn, it straightaway goes to the mill section where cloth is produced. But when that yarn comes to the handloom weaver, it has to undergo so many processes and he has to bear so many charges. Bundling, haling, transport and other charges and excise duties will be added, and this is a very great burden to the handloom weaver in competing with the textile mills. That is the position that the handloom industry is facing now. In order to give relief to the handloom weavers, the yarn rate should be brought down and it should be supplied to the handloom weavers at the rate at which the composite mills are getting. If this kind of concession is given, the handloom industry will be able to stand in the market.

Then. Sir, in the handloom industry they are using some chemicals, dyes and other tilings. But some excise and other duties have been imposed on these. Take, for example, soda, soda ash and other things. Millions of people are depending upon this handloom industry and they have to use dyes and chemicals, for continuing their handloom industry. Unless these duties are removed they cannot stand in the market. They are not able to compete with these powerlooms and the textile mill industry. I, therefore. request the Finance Minister to consider the representations that have been sent to him. The Finance Ministry has to examine all these things—to give relief and remove the excise and other duties levied on dyes and chemicals which are used by the hand-loom industry. Also, I request the Government of India to consider their policy on textile industries again and make a definite reservation for the- handloom industry: that is, bordered saris and dhoties should be exclusively reserved for the handloom industry. Then only this industry will stand and lind its proper place in India, and millions of people will make a living from this industry. Unless these facilities are given, the handloom industry will face a very critical situation and the people who are dependent on this industry will have to suffer.

Regarding export of handloom pro-ducts, recently we heard that the handloom products used to go to Nigeria, South African countries and some of the European countries. But these markets had not been properly utilised and they have stopped importing our handloom goods. On ac-i mm of this, there is a very big setback in the handloom industry and we are not able to export our goods to other countries. I, therefore, request the Finance Minister to take such steps as would promote the export of our handloom goods to other countries, and see that our foreign embassies are properly ins true ted so that markets for our hand loom products are properly explored and wc have a good sale in foreign markets, and our handloom weavers gel a fair wage and a fair living. In this connection, I would also congratulate the Finance Ministry on one step taken In them. They removed the duty on power driven motors In order to give relief to the agricultural community. It is a good thing and I appreciate it. Many Members have expressed that the Government has not taken proper steps in order in improve food production in the country. In the agricultural sector the steps taken by the Government

are to be appreciated. Research stations attached to the agricultural industry must be strengthened. More hybrid varieties in cotton and commercial crops like groundnut, sugar-cane and other things have also to be introduced so that our national income goes up, so that the standard of living of the common man can be increased.

Then, regarding the famine-affected areas, no permanent measures for relief have been suggested nor have necessary funds been allocated for such areas. In Andhra Pradesh there is an area called the Rayalaseema where once in every two years we suffer from famine. Lakhs of rupees are spent there for giving temporary relief, but no permanent eradication has been effected. I request the Government of India to take note of these famine and drought-affected areas and I suggest that underground water should be tapped in those areas which is the only solution through which we can improve the condition of the rural areas and the people who are dependent on land in the villages. I would request the Finance Minister to bestow his attention on this problem and allocate large sums of money for eradicating the famine conditions permanently from the Ra-yalaseema area. I would suggest that for tapping ground-level water a commission may be constituted, a statutory body may be appointed in order to suggest ways and means to improve the condition of the famine-affected areas in the Rayalaseema area. So many measures have been taken by the Government of India till now, but these measures have been taken only on a temporary basis. Whenever there is famine they send some grants and loans to the State Government and the State Government is in turn passing on these sums to those areas which they are spending there. But that is not adequate. I, therefore, request that a permanent solution be suggested in order to bring those backward famine-stricken areas on a par with other areas. The people of those backward areas are all dependent on agriculture. 20-6 RSS/ND/69

Andhra Pradesh, as you know, is a granary of foodgrains. It is supplying foodgrains to the country. Big projects have been taken up there. The Nagarjunasagar project is under completion. Due to lack of funds its work has been slowed down. There is the Pochampadu project on the Godavari river. It is in the Telan-gana area. It is to cover nearly four or five districts. Lakhs of acres will come under cultivation there. I, therefore, request that the Pochampadu project may be given top prio-rity. As you know, in Telangana we are seeing how the Telangana people are agitating that their area has been neglected and that their development programmes have not been properly tackled. In view of all these things the Government of India should allot more funds for the completion of the Pochampadu project immediately so that those backward areas may be developed.

Then, we have the Srisailam power project. This is a power project on the river Krishna. In reply to one of the questions asked during the last session I heard that this project would be completed in the year 1974-75. We are now in the year 1969 and it will take five or six years to complete the project. This is a big power project started some ten years back and Panditji laid the foundation for this project. The Andhra Pradesh Government thought that after the completion of the Srisailam project the power rate per kilowatt would go down and that the area could be industrialised as also the agricultural sector strengthened. I request the Government of India to take into consideration all these things and allot more funds for completing the same soon.

There is another thing I would like to bring to your notice. An All-India Handloom Fabrics Cooperative Society has been organised with headquarters at Bombay. The Society has applied for a loan of Rs. 25 lakhs for exporting handloom cloth from our country. But the Government has given only Rs. 10 lakhs. With

I Shri Sanaa Narayanappa]

this meagre amount how can they produce all the varieties that are required in other countries? I request that the All-India Handloom Fabrics Cooperative Society may be given at least Rs. 25 lakhs as loan in order to boost up their export scheme, in order to give a good standard of living to the people who are working in the Fabrics Cooperative Society. In all these matters I request the Government to give top priority to the development of handloom industry and the backward areas in the country.

Finally there is one more thing, Sir, that is regarding the salaries and allowances of the Members of Parliament. The report of the Joint Committee of the two Houses is ready and I would request the Government to take immediate steps in order to finalise . . .{Interruptions)

SHRI AKBAR ALI KHAN: Let the Opposition take the lead, not the Congress.

SHRI SHERKHAN (Mysore): Let him say that. He is free and he can express his views.

SHRI SANDA NARAYANAPPA: I am mentioning it because the Bill relates to finances. I suggest that the salaries and allowances of the Members may be discussed soon and I hope the Bill will be passed by both the Houses.

With these words I thank you, Sir.

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभापति महोदय, इस विधेयक के केवल एक या दो मदों पर ही मैं अपना मत व्यक्त करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। यह बहुत बड़ा विधेयक है और बहुत बड़ी धनराशि से सम्बन्ध रखता है।

श्रीमन्, मुझे सब से पहले शिक्षा के विषय पर कुछ प्रकाश डालना है। स्वतंत्रता के बाद जितना ध्यान इस विषय की ओर देना चाहिये था उतना नहीं दिया गया। यहां जब कभी भी शिक्षा के विषय में प्रश्न उठता है तो यह कह कर टाल दिया जाता है कि यह तो राज्य का विषय है और पैसा बहुत कम है या नहीं है। मैं यह समझता हूं कि यदि कोई आवश्यक विषय है, जो आधार है, जो बेस है, जिस पर सारे राष्ट्र की एकता निर्भर है, जिस पर जितनी भी योजनाएं यहां पर बन रही हैं उनकी सफलता निर्भर है, जिस पर कैसे यहां के नागरिक होने चाहिये यह निर्भर करता है, जिस पर कैसा हमारा राष्ट्र होना चाहिये यह निर्भर करता है, तो वह केवल शिक्षा है। मैं तो बहुत कुछ सोचने के बाद भी यह समझ नहीं पाया कि जिस समय हमारे बड़े लोगों ने विधान बनाया था उस समय उन्होंने शिक्षा को राज्य का सब्जेक्ट, स्टेट सबजेक्ट, क्यों बना दिया। सेंट्रल सबजेक्ट्स जो हैं मैं यह समझता हूं कि उनसे भी सर्वोपरि यदि कोई सब्जेक्ट है, यदि कोई विषय है तो वह शिक्षा का विषय है।

श्रीमन्, शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य है मानव को मानव बनाना और अच्छे नागरिक पैदा करना। केवल डाक्टर, इंजीनियर, या यह जो ब्युरोक्रैसी का कारखाना चला हुआ है उसका पुर्जा बना कर के तैयार कर देना, क्या केवल शिक्षा का यही उद्देश्य है? मैं समझता हूं, नहीं। आज जितनी भी समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं वे सब इसी कारण से हैं कि हमने इस विषय की अवहेलना की है, हम इस विषय की ओर उदासीन रहे हैं।

श्रीमन्, प्रत्येक राज्य में अलग-अलग प्रणाली है, अलग-अलग पुस्तकें हैं, अलग-अलग सिलेबस है। मैं स्वयं महसूस

कर रहा हूं, मेरे बच्चे उत्तर प्रदेश में पढ़ते हैं, यहां लाना चाहता हूं, किन्तु कठिनाई है उनके लिए सारी पुस्तकें बदल जायंगी, माध्यम बदल जायगा, सबजेक्ट बदल जाएंगे और बार-बार यह सोचने पर विवश होना पड़ रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के बच्चों को यहां लाकर दाखिल कराया जाय। आज नेशनल इन्टीग्रेशन, भावात्मक एकता की आवाज बुलन्द की जा रही है। कैसे वह एकता होगी। शिक्षा में भी एकता नजर नहीं आ रही है। यहां का व्यक्ति जब मद्रास में जाता है तब अपने आपको बिलकुल अजनबी पाता है, कुछ जानता नहीं है? हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से दक्षिण भारतीय भाई है, जब उनके बच्चे हमारे यहां स्कूलों में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिलकुल अनपढ़ हैं, कुछ जानते नहीं है। उनको कितना समय लगता है?

श्री अकबर अली खान: मीडियम की वजह से।

श्री मानसिंह वर्मा: मीडियम का कारण नहीं है, अनेक कारण हैं। क्षमा करेंगे नवाब साहब।

श्री चित्त बासु: यह नवाब हैं?

श्री अकबर अली खान: नहीं, मजदूर।

श्री मानसिंह वर्मा: शिक्षा के क्षेत्र में मैं 15 वर्ष तक कार्य करता रहा हूं। मैं समझता हूं कि यदि राष्ट्रीयकरण किसी विषय का होना चाहिये था तो केवल शिक्षा का ही होना चाहिए था। आज और चीजों का राष्ट्रीयकरण करते चले जा रहे हैं, पीछे पड़े हैं राष्ट्रीयकरण के। पब्लिक एन्टरप्राइजेज़ हम पैदा कर रहे हैं। हर चीज के लिए होड़ लग रही है कि राष्ट्रीयकरण होना चाहिए किन्तु जिस चीज का, जिस विषय का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए था वह शिक्षा है। कितनी बड़ी सुविधा होती सारे देश के अन्दर अगर शिक्षा का माध्यम एक होता, एक सा स्तर होता। कहने को कहते हैं कि पंजाब की मेथेमेटिक्स बहुत अच्छी है, मद्रास की अंग्रेजी बहुत अच्छी है। यू० पी० का क्या अच्छा है कुछ कह नहीं सकते।

एक माननीय सदस्य: हिन्दी।

श्री मानसिंह वर्मा: हां, वहां की हिन्दी अच्छी है, वहां की बंगाली अच्छी है। अगर इस प्रकार से अच्छाई होगी तो वह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि आज जो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है, जिसके कारण हमारी सारी योजनाएं सफल हो सकती हैं वह शिक्षा है। शिक्षा को यह कह कर कि वह प्रदेश का सब्जेक्ट है नजरन्दाज नहीं किया जा सकता, उसकी ओर उदासीनता नहीं दिखाई जा सकती। वह आपकी जिम्मेदारी है इसलिए क्योंकि यह राष्ट्र है और पूरे राष्ट्र को आप चला रहे हैं। इसकी हानि और लाभ आपके ऊपर डिपेन्ड करती है। आज हमारा बच्चा क्या बन कर निकल रहा है? वह समस्या आज हमारे सामने आ रही है। अनुशासनहीनता एक बड़ी विडम्बना बन कर हमारे सामने आ रही है। क्यों आ रही है, क्यों कि स्वयं हमने बनायी हैं। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है "To make the best of the man". अच्छे मानव उत्पन्न करना। यह हमारा सर्वोपरी सिद्धान्त होना चाहिए। क्या हमने बनाया? आज पुरानी सब बातों को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। जो पुरानी बात करते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये रिएक्शनरी हैं, प्रति-

[श्री मानसिंह वर्मा]

क्रियावादी है, पुरानी बातें ढूंढ़ते हैं, रूढ़िवादी हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि जो पुरानी बातें अच्छी हैं उनको लेने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए और मैं आज ऐसा मानता हूं कि आज वे पुरानी बातें शिक्षा के क्षेत्र में आ जायं तो आज शिक्षा का क्षेत्र भी उतना ही अच्छा हो जाय जैसा कि वह उस समय गौरवशाली था जबकि दूसरे देश वाले इसको गुरु मानते थे। आज हमारा बच्चा क्या बन रहा है? शिक्षा के द्वारा क्या उसको हम दिशा दे पा रहे हैं? इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं और केन्द्र से जो रुपया एजूकेशन के लिए दिया जाता है उसको देख कर बड़ी निराशा होती है।

समाजवाद का नारा लगाया हुआ है। अर्सा हो गया समाजवाद कहते कहते। समाजवाद का नंगा चित्र देहात के स्कूलों में देखिए। क्या समाजवाद नजर आ रहा है? मुझे पहले भी एक बार मौका मिला था तो मैंने कहा था कि आज वहां पर जो स्कूल बने हुए हैं, जो स्कूल देहात में चल रहे हैं वहां बैठने के लिए बच्चे को टाट की पट्टी भी मयस्सर नहीं है और दूसरी तरफ वे बच्चे हैं जिनके ऊपर 5--5 सौ रुपए खर्च होते हैं, ग्वालियर में स्कूल है सिन्धियां का, देहरादून में दून स्कूल है। इस प्रकार जो पब्लिक स्कूल चल रहे हैं वहां 300, 400, 500 रुपए तक एक बच्चे के ऊपर खर्च किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि स्टैंडर्ड आफ एजूकेशन बहुत बढ़ गया है। किसके लिए बढ़ गया है? कौन लाभान्वित हो रहा है? कौन लाभ उठा रहा है इसको देखने की आवश्यकता है। मुझे देहा तमें छोटे-छोटे स्कूलों में जाने का मौका मिला है इन्स्पेक्टर आफ स्कूल होने के नाते और मैंने देखा है--मैं निमंत्रण देता हूं मंत्री महोदय को कि मेरे साथ चलें और जाकर देखें कि स्कूल के बच्चों की देहात के अन्दर क्या स्थिति है--कि उन बच्चों के लिए न तो बैठने के लिए टाट है और न उनके तन पर कपड़ा है और न ही किताबें मौजूद हैं। और गुरुजनों के विषय में क्या कहूं। वह एक बड़ी विडम्बना है जिसके बारे में कहते हुए दुख होता है, रोना आता है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देश का बेस्ट ब्रेन होना चाहिए था, सबसे अच्छा मस्तिष्क होना चाहिए था, सबसे उच्च स्तर के हमारे गुरुजन होने चाहिए थे लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिनके हाथों में हमारी भावी संस्कृति है वे कैसे लोग हैं यह कहते हुए बड़ी शर्म आती है। जिनको कहीं पर, किसी और दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलती वह कहता है कि चलो मास्टरी करेंगे rejected from every corner इस प्रकार के लोग शिक्षा में आते हैं, अध्यापक बनते हैं और उनके हाथों में हमारी औलाद जाती है, बच्चे जाते हैं और किस प्रकार के बन कर वे निकलते हैं।

मुझे याद आता है हमारा शत्रु देश है चीन, लेकिन मैं आपको उदाहरण देता हूं। जब मित्रता चल रही थी तब मेरे एक मित्र एजूकेशन के आदान-प्रदान के सिलसिले में एक शिक्षक बन कर चीन में चले गए। जाते ही उनसे पूछा गया

"Are you married?". 'No Sir'. "Go back to your country, get yourself married and then come back".

उसको यहां आना पड़ा 15 दिन के लिए। हमने इलाहाबाद के एक अनाथालय की लड़की से जल्दी उसकी शादी कराई

क्योंकि बेचारा वह स्वयं बड़ा गरीब था, कहीं जल्दी से रिश्ता नहीं हो सका तो एक अनाथालय की लड़की से शादी कराई और फौरन ही उसको लेकर वहां पहुंचा। उसके बाद वहां से जो चित्र भेजा था उसको देख कर प्रसन्नता होती है? उसने लिखा कि मेरे लिए हर प्रकार की सुविधा है। जिन चीजों की जीवन के लिए आवश्यकता है वे सब मुझे मिली हुई हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त सी० आई० डी० इस बात की खोज करती है कि कहीं मिया-बीबी में आपस में झगड़ा तो नहीं होता, कोई प्राब्लम तो नहीं है, घर की समस्याएं तो नहीं हैं? इस कारण कि अगर घर की समस्याएं होंगी तो यह व्यक्ति काम नहीं कर सकेगा। इसके हाथ में हमारी आगे आने वाली औलाद है, आगे आने वाली संतति है जो आगे चल कर हमारे नागरिक बनेंगे। आज हमारा अध्यापक स्कूल में जाता है तो उसको फिक्र रहती है कि मेरी लड़की की शादी कैसे होगी, बैठा-बैठा सोचता रहता है, इसके अतिरिक्त 4-5 ट्यूशन करता है जिनकी चिन्ता लगी रहती है कि ट्यूशन में जाना है छुट्टी के बाद। थका होता है लेकिन तब भी ट्यूशन पढ़ाएगा क्योंकि उसका गुजारा नहीं होता। इसके अतिरिक्त इस प्रकार के लोग आते हैं जैसा मैंने कहा। आज जगह-जगह साइकोलोजिकल सेन्टर्स खुले हुए हैं। प्राचीन काल में साइकोलोजिकल सेन्टर्स नहीं थे लेकिन आचार्य इस बात की दीक्षा देते थे कि यह लड़का क्या बनेगा, कौन से सब्जेक्ट में यह पारंगत होगा, किस विषय में पंडित होगा और उस विषय का पंडित बन कर वह शिक्षा दिया करता था। आज ऐसी बात नहीं है। जैसा मैंने कहा, जो सब तरफ से मायूस हो जाता है उसको अध्यापक बना दिया जाता है। मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा कि इस विषय की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, विशेष रूप से अध्यापक वर्ग की ओर। आज जो यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े प्रोफेसर हैं उनका दर्जा आई० ए० एस० आफीसर से कम रखा गया है क्योंकि आई० ए० एस० आफीसर बहुत बड़ी चीज है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, प्रशासन करता है लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटर को बनाने वाला, उस आई० ए० एस० को बनाने वाला जो अध्यापक है वह आज बेगर की तरह, भिखारी की तरह रहता है, उसकी इज्जत नहीं होती। जिस देश के अंदर अध्यापकों के प्रति यह श्रद्धा हो, अध्यापकों के प्रति यह भाव हो वह देश क्या पनप सकता है? उस देश में क्या तरक्की हो सकती है? आज जितनी भी समस्यायें हमारे सामने आ रही हैं उनका सब से बड़ा कारण यह है कि आज तक हमने इस विषय को नजरअंदाज किया है क्योंकि कमाऊ बेटा तो यह है नहीं। शिक्षा कमा कर कुछ देने वाली नहीं है। यह तो खर्च ही कराती है इस लिये इस की तरफ से उदासीनता आ गयी है। यह नहीं सोचा गया कि यह मस्तिष्क है। अगर मस्तिष्क अच्छा होगा तो सारा शरीर अच्छा चलेगा। अगर हमारे बच्चे अच्छे नागरिक बनेंगे, उनका चरित्र अच्छा होगा, उन की शिक्षा अच्छी होगी तो वे बड़े हो कर भी अच्छे नागरिक रहेंगे और जब उन के द्वारा राष्ट्र का संचालन होगा तो वह सचमुच एक गौरव की चीज होगी।

SHRI AKBAR ALI KHAN: It is an investment.

श्री मानसिंह वर्मा: यह सोचता कौन है! यही तो मैं भी कह रहा हूं कि इस को इन्वेस्टमेंट कर के कौन

[श्री मानसिंह वर्मा]

सोचता है। तो मेरा निवेदन है कि शिक्षा की केन्द्रीय योजनायें होनी चाहिये। रूरल एरियाज में भी अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के अच्छे-अच्छे स्कूल होने चाहिये कि जिन में गरीब बच्चे भी अच्छे स्तर पर अच्छी तालीम हासिल कर सकें। यह होना चाहिये। क्यों नहीं हो सकते है। मैं देखता हूं कि सोशल वेलफेयर में वजीफे दिये जाते हैं। इस प्रकार से रुपया बर्बाद किया जाता है। मैंने अक्सर कहा है कि इस तरह से वजीफे देने से कोई लाभ नहीं है। आप अच्छे सेन्टर, अच्छे स्तर के स्कूल कायम कीजिये और उन का संचालन केन्द्र के द्वारा होना चाहिये और इस के साथ ही सब स्थानों पर, सारे सेंटर्स में एक सा सलेबस होना चाहिए, एक सा काम होना चाहिये, एक से इंस्ट्रक्शन्स होने चाहिये, एक सी शिक्षा उन को मिलनी चाहिये और अच्छे से अच्छे अध्यापकों के द्वारा उन का संचालन होना चाहिये। अगर ऐसा हो तो मैं नहीं समझ सकता कि क्यों नहीं अच्छे नागरिक पैदा होंगे। आज वह स्थिति आ रही है कि हम परेशान हैं। आज मैं सुबह आ रहा था, मैं ने देखा कि जिस तरह से हमारे नौजवान व्यवहार करते हैं, हालांकि वे हमारे बेटे हैं, हमारे बच्चे हैं, लेकिन उसे देख कर हमारा सिर लज्जा से झुक जाता है। यह इस लिये हुआ है कि उन को कोई दिशा नहीं दी जा रही है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिये विशेष प्रबन्ध होना चाहिये। अध्यापकों को बिलकुल निर्द्वन्द कर देना चाहिये ताकि उन के लिये अपने घर की समस्यायें न रहें और उन के लिये कसौटी ऐसी होनी चाहिये कि जो अच्छे से अच्छे विद्वान हों वे ही इस लाइन में आयें। इस के लिये केवल यही नहीं होना चाहिये कि उन के पास चार, पांच डिग्रियां हों, बल्कि हमें देखना चाहिये कि उन का चरित्र कैसा है, उन की कर्त्तव्य-गरिमा कितनी है। मेरा अनुभव है कि टीचिंग लाइन में जो फर्स्ट डिवीजनर्स होते हैं वे थर्ड क्लास लाते हैं और जो थर्ड क्लास होते हैं वे टीचिंग प्रेक्टिस में फर्स्ट क्लास साबित होते हैं। पढ़ाने का एक तरीका होता है। हर एक आदमी सफल अध्यापक नहीं बन सकता। जो इस प्रकार से शिक्षा का काम करना चाहते हैं उन के अंदर से यह चीज पनपती है कि हम शिक्षक बनेंगे। तो इस लिये कड़ी कसौटी होनी चाहिये और उन को कसौटी पर कसने के बाद, अच्छे स्तर का पाने के बाद उन को शिक्षा विभाग में लेना चाहिये, तब उन की नियुक्ति होनी चाहिये और फिर उन को पूरा खर्चा ऐसा मिलना चाहिए कि जिस से उन को किसी प्रकार की कमी का अनुभव न हो।

एक छोटी सी दूसरी बात मैं कहूंगा समाज कल्याण की। समाज कल्याण भी विषय ऐसा है कि जो राज्यों को सौंप रखा गया है और केन्द्र की तरफ से इस के लिये इमदाद मिलती है, सहायता दी जाती है। प्लान्स बनते हैं, योजनायें बनती हैं। उन में दिखलाया जाता है कि समाज कल्याण के लिये इतना रुपया दिया जा रहा है। किन्तु उस का परिणाम क्या निकल रहा है? कितना समाज कल्याण आज तक हो पाया है इस को अगर हम देखते हैं तो हम को निराशा ही होती है। अभी बहुत कुछ ऊधम मच चुका है पिछले 15 दिन या महीने भर के अंदर कि देश के अंदर से अस्पर्श्यता समाप्त नहीं हुई है, बल्कि किसी किसी जगह

तो यह जातीयता और भी उभर कर सामने आ गयी है। बजाय इस के कि यह समाप्त होती यह उभर कर सामने आयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि जातीयता को समाप्त करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह भावना कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह ऊंचा है, यह नीचा है, यह ब्राह्मण है, यह राजपूत है, इस को खत्म करने के लिये क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया। एक छोटी बात थी कि सब लोग जाति-सूचक शब्द अपने नामों के साथ न लगायें। लेकिन आज तक सरकारी दफ्तरों में जाति पूछी जाती है, कचहरी में भी जाति पूछी जाती है और वह अस्पर्श्यता आप के सेक्रेटेरियेट में भी बर्ती जाती है कि एक व्यक्ति अपना पानी अलग रख लेता है। मेरे पास इस तरह की मिसालें हैं। (*Time bell rings*) मैं दो चार मिनट और लूंगा। तो अगर 22 वर्ष के बाद हम अस्पर्श्यता समाप्त नहीं कर सके तो आज हम उस के लिये दोष देते हैं उन लोगों को कि जो रूढ़िवादी हैं, लेकिन हमारी तरफ से इस के लिये क्या किया गया है। रिप्रेजेन्टेशन्स होते हैं, रिजर्वेशन्स होते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है सरकार का कि जहां पर रिजर्वेशन पूरा हो। ब्लैंक है सब जगह। बहुत कम है। आप फीगर्स ले लीजिये। जब जब हम ने फीगर्स मांगे हैं, पूरा ब्योरा तो नहीं मिला, लेकिन वह निराशाजनक है। अभी पेरुमल कमेटी की रिपोर्ट निकली है। उस से पता चल जायगा कि आज तक समाज कल्याण के लिये क्या हुआ है। यह होना चाहिये था। हां, कुछ मुझे ऐसा लगता है कि आप ढोल तो बहुत पीटेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। केवल यह वोट-कैचिंग डिवाइस है। यह नारा है कि हम कल्याण कर रहे हैं ताकि लोग समझें कि इन के अलावा कोई दूसरा हमारा आका नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं कि अस्पर्श्यता की बीमारी राजनीतिक नहीं है, यह सामाजिक बीमारी है। यह राजनीति से दूर नहीं हो सकती। आप एक आदमी को मिनिस्टर बना दीजिये या कोई बड़ा पद दे दीजिये, लेकिन जब तक समाज में उस को छोटा समझा जायगा तब तक वह तो किसी काम का नहीं है। मैं कहता हूं कि सड़क में झाड़ू देने वाला हमारा भाई है, गली में झाड़ू देने वाला हमारा भाई है, वह अपना काम करते हुए भी हम से बराबरी का दावा कर सकता है यह होना चाहिये, यह मनोवृत्ति सब की होनी चाहिये। इस के लिये हम वातावरण उत्पन्न नहीं कर सके, आज तक नहीं कर सके क्योंकि उस राजनीतिक प्रवृत्ति ने, उस राजनीतिक नारे ने सब को दबा कर रख दिया और आज उस ने समाज कल्याण न कर के एक हरिजन वर्ग अलग बना कर खड़ा कर दिया है। वह एक अलग वर्ग बन गया। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हम वर्ग-विहीन समाज की रचना करना चाहते हैं और दूसरी तरफ अलग वर्ग बना कर खड़ा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज इंस्ट्रास्पेक्शन की आवश्यकता है। हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हमारी जो योजनायें हैं, किस प्रकार से उन का कार्यान्वियन हुआ है, किस प्रकार से उन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। यह ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। इतना रुपया जो बर्बाद हो रहा है उस

[श्री मानसिंह वर्मा]

का कुछ नतीजा निकल रहा है या नहीं। इस को देखने की आवश्यकता है। मेरा समय समाप्त हो गया है। कहना बहुत कुछ चाहता था। मैं फिर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वह शिक्षा की ओर और समाज कल्याण की ओर विशेष ध्यान देने की कृपा करें। धन्यवाद।

THE VICE CHAIRMAN (SHRI D. THENGARI): The House stands adjourned till 11 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at twenty minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 7th May, 1969.

M -ilPCBE—S2—6 RSS/ND/69—19-12-69—570